कामयाबी के दो वर्ष

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

NITI AAYOG

DDU-GKY
Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushal Yojana
Empowering India • Powering the World

Smart City
MISSION TRANSFORMANATION

N·S·D·C
National Skill Development Corporation

PMKVY
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA
MERA KHATA BHAGYA VIDHATA

MAKE IN INDIA

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

SOIL HEALTH CARD
Swasth Dhara, Khet Haraa

Housing for all
Ministry of Housing & Poverty Alleviation

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जन आवास योजना
सरल निवास, सफल विकास

Atal Pension Yojana

Digital India
Power To Empower

SPMRF

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

कामयाबी के दो वर्ष

संकलनकर्ता

शिवानन्द द्विवेदी

Cover Design & Layout

Vikas Saini

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

रिसर्च फाउंडेशन

अनुक्रमणिका

क्र.सं	लेख	पेज न.
01	Foreword	4
02	प्राक्कथन	5
03	केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयीं जनहित योजनायें	8
04	मेक इन इंडिया– विकास में सहायक	21
05	उर्जा क्षेत्रः विद्युतीकरण क्षेत्र में परिवर्तनकारी कदम	24
06	जनता के सरकार के बीच कम हुआ फासला	27
07	JAM: जनधन, आधार, मोबाइल योजना	28
08	खादी कुटीर उद्योग : सरकार, बाजार और रोजगार	31
09	योग की बढ़ी अन्तरराष्ट्रीय साख **– शिवानन्द द्विवेदी**	35
10	दो साल का कामयाब सफर **– हर्ष. वी पंत**	38
11	मोदी सरकार का मूल्यांकन **– डॉ. एके वर्मा**	40
12	जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निर्णय लेने की क्षमता सरकार की बड़ी उपलब्धि **– भूपेन्द्र यादव**	43
13	Corridors of Power: Two years of NDA… a lot better than UPA **– Santosh Tiwari**	45
14	Two years of transformation: On NDA's second anniversary, Ujjwala heralds smoke free acche din for India's poor **– Amit Shah**	49

Foreword

A Number of Life-Altering Initiatives...

Two years of the BJP led NDA government has seen an unprecedented and multi-dimensional outreach and effort in all directions of national development. The outreach has percolated to the grassroots and has started making a difference in the lives of the vast majority of Indians who have hitherto been deprived of the fruits of growth. A number of socially transformative schemes, a number of socially elevating projects, a number of basic life altering initiatives – such as rural electrification undertaken in a time bound manner, or the DBT initiative which has enabled a large number of families to graduate from smoke choking cooking ovens to LPG ovens – have indeed begun transforming the lives and instilling hope in the system among millions of our citizens.

However the struggle is, as Prime Minister Modi, said between #Vikaasvad (attitude of development) and #Virodhvaad (attitude of opposing and obstructionism). Those who have failed to deliver on a number of basics during an uninterrupted period of five decades in power are being seen articulating the loudest opposition – an opposition that is without substance though and which only serves to delay the process of growth.

But undeniably every year – in the last two years – around this time round, the debate has turned towards development, performance, result, delivery and accountability. The Narendra Modi led government and its pattern of working has ensured that the issues discussed revolve around these and this is in itself is a positive development.

The compilations in this e-booklet brings together the various initiatives of the BJP led NDA government, collates discussions and analysis on them and presents these in a format that is easy to read and appealing and can be used by a large number of our workers to disseminate the affirmative message of development and inclusiveness.

I commend the SPMRF research team for making this effort.

Dr. Anirban Ganguly
Director
SPMRF

प्राक्कथन

सफलता की ओर सरकार

भाजपा-नीत मोदी सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं। पिछली संप्रग सरकार के कार्यकाल में देश में एक निराशा का माहौल बन गया था, जिससे निजात दिलाने का भरोसा लोगों को नरेंद्र मोदी में दिखा। उसी भरोसे का परिणाम था कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। अब जब भाजपा-नीत केंद्र सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं तो इस सरकार के दो वर्षों के कामकाज का मूल्यांकन होना स्वाभाविक है। हालांकि वर्षों की चरमराई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो वर्ष के कार्यकाल को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है, इसका अंदाजा देश की आम जनता को भी है। देश की आम जनता भी यह मान रही है कि सरकार की मंशा और दिशा दोनों सही है, तो परिणाम भी सही ही दिखेंगे। हालांकि इन दो वर्षों में कई मोर्चों पर तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार अपने वायदों की पूरा करने की दिशा में आगे बढती दिख रही है। केंद्र सरकार ने मेक इन इण्डिया, स्मार्ट सिटी, जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम, स्किल इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, विद्युतीकरण से संम्बधित योजनाओं, सड़क परिवहन, रेलवे आदि के क्षेत्र में जो काम किये हैं वो अद्भुत हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सरकार ने सभी के हितों का ख्याल रखा है। इन दो वर्षों में गरीब, गाँव और किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है। पिछला २०१५-१६ का बजट तो गांवों को समर्पित ही बताया गया है और विरोधी भी इसको लेकर असहमति नहीं जता पाए। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा कर रही है। खुदरा एवं थोक महंगाई दर में हुई कमी से अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने के संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति का अलग-अलग स्तरों पर अगर समग्र रूप से मूल्यांकन करें तो सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक खुदरा एवं थोक महंगाई दर में कमी हुई है। आद्योगिक विकास दर बढ़ा है एवं भारत में विदेशी निवेश की संभावना भी पहले की तुलना में बहुत अधिक हुई है। इसबार अच्छे मानसून के आसार भी दिख रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स को अगर आधार बनाकर भविष्य का आकलन करें तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था में और सुधार होने के स्पष्ट संकेत मिलते दिख रहे हैं। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार खुदरा महंगाई दर पिछले छः महीनों के निचले स्तर पर है। मार्च महीने खुदरा महंगाई दर छः महीने के न्यूनतम स्तर तक घटकर ४.८३ फीसद हो गयी थी। फरवरी में यह आंकड़ा ५.१८ फीसद पर था। हालांकि थोक महंगाई दर तो नियमित रूप से गिरावट की ओर है। भाजपा-नीत सरकार आने के बाद थोक महंगाई दर में नियमित रूप से गिरावट को महंगाई पर स्थायी नियंत्रण के रूप में देखा जा सकता है। चूँकि अगस्त २०१४ में थोक महंगाई दर ३.८४ फीसद थी जो कि सितम्बर २०१४ से अबतक शून्य से नीचे पहुँच चुकी है। थोक महंगाई दर को लेकर पिछले दिनों रायटर्स के सर्वे में यह अनुमान जताया गया था कि यह गिरावट -.७७ फीसद तक रहेगा लेकिन इसमें गिरावट का स्तर अनुमान से भी ज्यादा -०.८४ तक पहुँच गया। लेकिन खुदरा महंगाई दर में गिरावट को स्थिर करना सरकार के लिए अभी भी चुनौती है। हालांकि सरकार इस दिशा में सफलता पूर्वक काम कर रही है। महंगाई

के सन्दर्भ एक गौर करने वाली बात यह है कि थोक महंगाई दर में हो रही नियमित कमी इस बात का प्रमाण है कि सरकार अपने स्तर पर तो महंगाई को कम करने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है लेकिन खुदरा बाजार के मामले में अभी भी सरकार को व्यापक स्तर पर काम करने की जरुरत है। निचले स्तर पर महंगाई के कई कारण होते हैं, उनमे से कुछ मुख्य कारण कालाबाजारी एवं राज्यों सहित लोकल बाजारों के बीच सामंजस्य की कमी आदि हैं। वर्तमान केंद्र सरकार इन स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से गंभीर दिख रही है। उसी का परिणाम है कि अब खुदरा स्तर पर भी महंगाई दर में कमी में स्थिरता आ रही है। हालांकि इस स्थिरता को कायम और सुनिश्चित करने के दिशा में कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए व्यवहारिक स्तर पर सख्ती बरतने की जरूरत है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत से ही संबंधित मंत्रालयों के साथ बैठक करके कालाबाजारी को रोकने की दिशा में गंभीर कदम उठाने का निर्देश दिया है। खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर के बीच कम हो रहा अंतर, इस सरकार के कार्यों के लिहाज से एक अच्छा संकेत है। भविष्य में यह अंतर और कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

अर्थव्यवस्था के लिहाज केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि आद्योगिक विकास दर में हुई २ फीसद की वृद्धि है। लिहाजा आगामी वित्त वर्ष में भारत का विकास दर ७.७ फीसद रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोत्तरी की तरफ है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विकास दर वर्ष २०१६-१७ में ७.७ फीसदी रहने की उम्मीद है जो कि २०१७-१८ में ७.६ फीसदी तक पहुँच सकता है। विकास दर में बढ़ोत्तरी होने की वजह यह होगी कि इसबार मानसून अच्छे रहने के संकेत हैं और सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग को लागू किये जाने के बाद सरकारी सेवा के लोगों की खर्च सीमा में बढ़ोत्तरी होगी। चूँकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद लोगों की कमाई में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ निवेश में भी इजाफा होगा जिसका सीधा और सकारात्मक असर विकास दर पड़ेगा। सरकार को इस वर्ष मानसून से बहुत उम्मीदें हैं। चूँकि मानसून अगर अच्छा रहा तो रिजर्व बैक द्वारा नीति दरों में और कटौती की संभावना प्रबल है। गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों में भारत के लिहाज से मानसून की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। बावजूद इसके रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों लगातार कटौती की गयी है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा .२५ फीसद की कटौती के बाद ब्याज दर ६.५ फीसद तक पहुँच गया है। ज्ञात हो कि पिछले जनवरी २०१५ के बाद से अबतक ब्याज दरों में कुल १.५ फीसद की कटौती इस बात का संकेत है कि रिजर्व बैंक निवेश आदि की संभावना को लेकर उदारवादी एवं साहसी दृष्टिकोण अपनाए हुए है। वर्तमान में यह ब्याज दर पिछले पांच वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है। ऐसे में इसबात का पूरा अनुमान है कि अगर मानसून बेहतर रहा तो महंगाई दर में और कमी होगी एवं ब्याज दरों में भी और गिरावट देखने को मिलेगी। चूँकि ब्याज दरों में गिरावट से आवास, वाहन एवं अन्य क्षेत्रों में लोगों का निवेश बढेगा जो विकास की रतार को तेज करने में सहायक होगा। यहाँ पर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम की यह बात गौर करने लायक है जिसमे उन्होंने कहा है कि वृहत आर्थिक हालातों को सम्हालने की दिशा में भारत ने सही कदम उठाये हैं। जबकि कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं समेत अन्य अर्थव्यवस्थाएं चुनौतिपूर्ण वैश्विक हालात के बीच मुश्किल में हैं। ऐसे में भारत ने अपना घाटा कम किया है ताकि वह उतार-चढ़ाव भरे वैश्विक हालात में अपने अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए अपेक्षाकृत अधिक लचीलेपन के साथ काम कर सके।

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार ने व्यापक स्तर पर काम किया है, जिसका असर अभी उस ढंग से बेशक नही दिख रहा जितना कुछ साल बाद दिखेगा। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में भी भारत पर मजबूत भरोसा जताया गया है। दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित अपनी अपनी छमाही रिपोर्ट 'साउथ एशिया इकोनामिक फोकस' के हालिया संस्करण में विश्व बैंक की तरफ से यह विश्वास जताया गया है कि भारत की आर्थिक मजबूती वाले नेतृत्व में दक्षिण एशिया विश्व में सबसे तेजी से विकास करने वाला भू-क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर है। रिपोर्ट में इसबात का भी जिक्र किया गया है कि इस क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था के आकार की बुनियाद पर भारत दक्षिण एशिया के अर्थव्यवस्था का बुनियाद तय की स्थिति में खड़ा हो रहा है। विश्व बैंक के इस आकलन के पीछे की बड़ी वजह मानसून के बाद कृषि क्षेत्र में सुधारों की आशा है। दरअसल ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बेहतर मानसून का सीधा असर कृषि विकास दर पर पड़ेगा जिससे हमारे सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति में मजबूती आएगी। कृषि विकास दर के लक्ष्यों को पाने के लिए सरकार के स्तर पर तमाम प्रयास किये जा रहे हैं। तमाम योजनाओं जैसे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिचाई योजना के माध्यम से परंपरागत कृषि विकास योजना, फसल बीमा योजना आदि हैं। ऐसे में मानसून का साथ अगर सरकार को मिल गया तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर दौड़ने में वक्त नहीं लगेगा। हालांकि प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से कृषि की स्थिति अभी बहुत बेहतर नहीं हो पाई है लेकिन जिस स्तर पर सरकार नीतिगत रूप से प्रयास कर रही है, उससे जल्द ही बेहतर स्थिति को प्राप्त कर लिया जाएगा।

हालांकि इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार के प्रयासों में उपलब्धियों को लेकर विपक्ष का रुख कभी भी सकारात्मक क्यों नहीं रहता है। कई बार तो बेहद हास्यास्पद स्थिति तब हो जाती है जब कांग्रेस के लोग सरकार की नीतियों की यह कहकर आलोचना करते हैं कि अमुक नीति बिलकुल जनहित में नहीं है और फिर तुरंत यह भी कह देते हैं कि सरकार कांग्रेस की नीतियों को ही लागू कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पुख्ता आलोचना कर पाने वाला मुद्दा अभी तक विपक्ष के हाथ लगा नहीं है या यूं कहें तो मिला नहीं है। लेकिन आगामी छः महीना बेहद अहम् रहने वाला है। अगर इन छः महीनो में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को संतुलित करके खुदरा महंगाई दर के स्तर को कम करने में सफलता हासिल की गयी तो आलोचना के मोर्चे पर विपक्ष की स्थिति और निरीह हो जायेगी। हालांकि इस मामले में बहुत कुछ मानसून पर भी निर्भर करता है। फिलहाल सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान उन उपायों पर देने की जरूरत है जिनसे विकास दर के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और खुदरा महंगाई दर में कमी करते हुए उसे स्थिर किया जा सके। अभी तक तो सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है और उसका परिणाम दिखने लगा है। अभी तक के आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अच्छे दिनों की आहट सुनाई देने लगी है।

इस ई-बुकलेट के माध्यम से हमारा उद्देश्य सरकार के कार्यों को जनता के बीच ले जाना है। इस बुकलेट में तमाम लेख, जानकारियाँ मीडिया के विविध मंचों से ली गयीं हैं। हम उन सभी माध्यमों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जिनका लेख आदि इस बुकलेट में इस्तेमाल किया गया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद!

शिवानन्द द्विवेदी
रिसर्च फेलो,
डॉ श्यामा प्रसाद मुकर्जी रिसर्च फाउंडेशन

केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयीं जनहित योजनायें

प्रधानमंत्री जन–धन योजना

प्रधानमंत्री जन–धन योजना (संक्षेप में – पीएमजेडीवाई) भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा १५ अगस्त २०१४ को तथा इसका शुभारंभ २८ अगस्त २०१४ को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को ई–मेल भेजा जिसमें उन्होंने श्हर परिवार के लिए बैंक खाता को एक 'राष्ट्रीय प्राथमिकता' घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंको को कमर कसने को कहा। योजना के उद्घाटन के दिन ही १.५ करोड़ बैंक खाते खोले गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना

माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के ७५ वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष २०२२ तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एक व्यापक मिशन २०२२ तक सबके लिए आवास शुरू किया है। २५ जून २०१५ को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।

इस लेख में आप प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी यथा लाभार्थी, पात्रता, योजना में भाग लेने की संपूर्ण प्रक्रिया एवं योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सभी प्रश्न(एफएक्यू) एवं उनके उत्तर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

लाभार्थी:

लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। लाभार्थी परिवार के पास या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम वाली रिहायशी इकाइयां) नहीं होना चाहिए।

इस मिशन का उद्येश्य निम्नलिखित कार्यक्रम विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना है–

- भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लमवासियों का स्लम पुनर्वास।
- ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन।
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों एवं निम्न आय वर्ग सहित आर्थिक रूप से कमजोर तबके से जुड़े लाभार्थियों को आवास ऋण पर ब्याज सहायता बढ़ाकर ६.५० प्रतिशत तक करने की अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से शहरी गरीबों को करीब २.३०-२.३० लाख रूपये तक का फायदा होगा क्योंकि इससे उनकी समान मासिक किस्त करीब २,८५२ रूपये प्रति माह तक घट जाएगी। राजग सरकार की इस महती योजना को औपचारिक रूप से २५ जून को शुरू किया जायेगा और उस समय तक सरकार इसके क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी कर देगी। कुल मिलाकर अगले सात साल के दौरान शहरी इलाकों में २ करोड़ नए मकान बनाने के लिए राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन के तहत विभिन्न मदों के अंतर्गत एक लाख रपये से २.३० लाख रूपये के दायरे में केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

बेटी को बोझ ना समझें और ना ही उसके जन्म पर निराश हों, क्योंकि बिना बेटी के परिवार नाम की संस्था का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसी संदेश के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना को लांच किया। यह योजना बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के उद्देश्य से लांच की गई है। इस अनोखी योजना में खाता खुलवाना और इसके फायदे लेना बड़ा ही आसान

है। आईए जानते हैं कैसे खुलवाएं इस योजना के अंतर्गत अपनी बेटी का खाता ''सुकन्या समृद्धि खाता'' किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। बेटी के जन्म के समय या फिर १० साल की उम्र तक यह खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के समय कम से कम १००० रूपए और एक वित्त वर्ष में अधिकतम १.५ लाख रूपए जमा करवाने होते हैं। अगर आपकी बेटी ने योजना शुरू होने के एक साल पहले भी १० वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो ऐसी बेटियों के खाते भी खुलवाए जा सकते हैं। हालांकि एक बेटी के नाम से एक ही खाता खोला जा सकता है।

परिवार में अगर दो बालिकाएं हैं, तो दोनों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में दो से अधिक बालिकाओं का खाता इस योजना में नहीं जुड़वाया जा सकता है। हालांकि जुड़वां बच्चे होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर तीसरा खाता भी खुलवाया जा सकता है। बेटी के १० वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले खाते का संचालन अभिभावक ही करेंगे, लेकिन इसके पश्चात स्वयं खाताधारक बालिका भी खाते का संचालन अपने हाथ में ले सकेगी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है, जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ८ अप्रैल २०१५ को नई दिल्ली में की थी। मुद्रा बैंक के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हस्तक्षेप के तहत इसमें तीन श्रेणीयां है- शिशु, किशोर और तरुण ये तीनों श्रेणीयां लाभार्थियों को विकास और वृद्धि में मदद करेगी। मुद्रा बैंक फिलहाल एनबीएफसी के तौर पर काम करेगा। मुद्रा बैंक यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में १० लाख रुपये तक के सस्ते लोन दिए जाएंगे। शुरुआती दौर में मुद्रा बैंक सिडपी की यूनिट के तौर पर काम करेगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ३ तरह के लोन मिलेंगे। इनके नाम होंगे शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना के तहत ५० हजार रुपये तक के लोन दिए जाएंगे।

किशोर योजना के तहत ५० हजार रुपये से ५ लाख रुपये तक के लोन दिए जाएंगे। तरुण योजना के तहत ५ लाख रुपये से १० लाख रुपये तक के लोन दिए जाएंगे। मुद्रा बैंक से देश के करीब ५ करोड़ ७७ लाख छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। छोटी विनिर्माण ईकाई और दुकानदारों को इससे लोन मिलेगा। इसके साथ ही सब्जी वालों, सैलून, खोमचे वालों को भी इस योजना के तहत लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हर सेक्टर के हिसाब से स्कीम बनाई जाएगी। इन पर ब्याज की दरें रिजर्व बैंक के निर्देश के आधार पर तय होंगी।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अंशदाताओं को ३३० रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर २,००,००० रुपये के जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। पीएमजेजेबीवाई १८ से ५० वर्ष की आयु समूह के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका कोई बैंक खाता होगा जिसमें से ''स्वतः डेबिट'' सुविधा के जरिए प्रीमियम वसूल किया जाएगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत मात्र १२ रूपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रूपये का दुर्घटना कवर मिलता है।

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदाताओं को ६० वर्ष की आयु पूरी होने पर १००० रुपये से लेकर ५००० रुपये तक प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, जो उनके अंशदान पर निर्भर करेगी। यह अंशदान किसी व्यक्ति के योजना में शामिल होने के समय उसकी आयु के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। केंद्र सरकार पात्र अंशदाता के खाते में हर वर्ष कुल अंशदान का आधा हिस्सा अथवा १००० रुपये, इनमें जो भी कम हो, जमा कराएगी। यह अंशदान ३१ दिसम्बर, २०१५ से पहले नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल होने वाले अंशदाताओं के खाते में ५ वर्ष अर्थात २०१५-१६ से २०१९-२० तक जमा कराया जाएगा। किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य और आयकरदाता इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकेंगे। अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी/पति को पेंशन मिल सकेगी और उसके बाद पेंशन निधि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु १८ वर्ष और अधिकतम आयु ४० वर्ष होगी। सरकार न्यूनतम नियत पेंशन लाभ की गारंटी प्रदान करेगी।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है। जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र

मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन ११ अक्टूबर २०१४ को शुरू किया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों में विकास और बुनियादी ढाँचे रखने हेतु सभी राजनीतिक दलों के सांसद को इस योजना के तहत गाँव को गोद लेना है और २०१६ तक उसे आदर्श गाँव बनाना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नें १३ जनवरी २०१६ को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना न करें। यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जायेगी। एसोसिएशन में के निपटान की प्रक्रिया बनाने का फैसला किया गया है। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

- किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल २ प्रतिशत एवं सभी रबी फसलों के लिए १.५ प्रतिशत का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल ५ प्रतिशत होगा।
- किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम ९० प्रतिशत हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।
- काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु

स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

- २०१६-२०१७ के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन ५,५५० करोड़ रूपये का है।
- बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
- पीएमएफबीवाई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) की एक प्रतिस्थापन योजना है और इसलिए इसे सेवा कर से छूट दी गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का लक्ष्य हर एक किसान के खेत को सींचना और 'प्रति बूंद अधिक फसल' की व्यवस्था करने के लिए पानी का प्रभावी इस्तेमाल करना है। बजट में सूक्ष्म् व सिंचाई, जल संभरण विकास और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ५,३०० करोड़ रुपये की राशि के आवंटन का प्रावधान किया है। श्री जेटली ने राज्यों से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भरपूर योगदान देने का अनुरोध किया है।

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना

इस योजना का शुभारम्भ १ जुलाई २०१५ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी। इस योजना का उद्देश्य सस्ती एवं जेनरिक दवाइयों को सरकारी औषधि केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराना है।

मेक इन इण्डिया

मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर जोर देने के लिए बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने २५ सितम्बर २०१४ को किया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने २५ सितम्बर २०१४ को विज्ञान भवन के कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी।

स्वच्छ भारत अभियान

'स्वच्छ भारत' भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गाँधी के जन्मदिवस २ अक्टूबर २०१४ को आरम्भ किया गया। महात्मा गांधी ने अपने

आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था।

किसान विकास पत्र

किसान विकास पत्र केंद्र सरकार की एक योजना है। यह निवेश का दीर्घकालिक जरिया है। जिसका लाभ डाकघर से लिया जा सकता है। इसमें निवेश किया जाता है। इसमें न्यूनतम निवेश १०० रुपए तक किया जा सकता है।

इसकी परिपक्व समय अवधि आठ साल की होती है। इन आठ साल में डाकघर आपके निवेश पर ८.४० फीसदी का ब्याज लगाकर देता है। किसान विकास पत्र के तहत आपको अपना जन-धन किसी अपने करीबी को ट्रांसफर करने की सुविधा होती है।

सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम

इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी २०१५ में किया था। कृषि क्षेत्र में इस योजना को बहुत कारगर माना गया है।

डिजिटल इण्डिया

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं-

१. डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना,

२. इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना,

३. डिजिटल साक्षरता।

योजना को २०१६ तक कार्यान्वयित करने का लक्ष्य है। एक टू-वे प्लेटफॉर्म का निर्माण

किया जाएगा जहाँ दोनों (सेवा प्रदाता और उपभोक्ता) को लाभ होगा। यह एक अंतर-मंत्रालयी पहल होगी जहाँ सभी मंत्रालय तथा विभाग अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाएंगें जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा आदि। चयनित रूप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को अपनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना केंद्र के पुनर्निर्माण की भी योजना है। यह योजना मोदी प्रशासन की टॉप प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। यह एक सराहनीय और सभी साझेदारों की पूर्ण समर्थन वाली परियोजना है। जबकि इसमें लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी, नागरिक स्वायत्तता हनन, तथा भारतीय ई-सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी की कमी तथा भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियाँ भी हैं। डिजिटल इंडिया को कार्यान्वयित करने से पहले इन सभी कमियों को दूर करना होगा।

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ५ नवंबर २०१५ को तीन स्वर्ण संबंधी योजनाओं की शुरुआत की। ये योजनाएं हैं:- स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, सार्वभौम गोल्ड बांड योजना और भारतीय स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना बैंक में सोना अल्पावधि (१-३ वर्ष), मध्यमावधि (५-७ वर्ष) और दीर्घावधि (१२-१५ साल) के लिए रखने का अवसर प्रदान करती है। डिपाजिट रखे गए सोने पर ब्याज प्राप्त होगा, और वह पूंजी लाभ सहित कई अन्य करों से मुक्त होगा। सावरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना के तहत निवेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए बांड पत्र खरीद सकेंगे। २४ कैरेट का सोने का सिक्का निकालने की भी योजना है। देश में इस तरह की यह पहली योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोई कारण नहीं है कि भारत को गरीब देश कहा जाए, उसके पास २०,००० टन सोना है।

स्किल इण्डिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारम्भ युवाओं को स्किल्ड बनाने और रोजगार हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया। रोजगार के लिए यह एक कारगर योजना साबित हो रही है।

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

बेटी बचाओ बेटी पढाओ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP) महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रुप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत २२ जनवरी २०१५ को की गई। जिसे निम्न लिंगानुपात वाले १०० जिलों में प्रारंभ किया गया है।

मिशन इंद्रधनुष

मिशन इन्द्रधनुष का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा २५ दिसंबर २०१४ को किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य जन्म से लेकर दो साल तक के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को सात प्रकार की बीमारियों से रोकथाम के टीके लगाना हैं। यह सुनिश्चित करना हैं। ''मिशन इन्द्रधनुष'' का उद्देश्य इन्द्रधनुष के सात रंगों वाले हमारे जीवन में किसी भी तरह की टीका निवारणीय बीमारियों के खिलाफ सभी बच्चों का टीकाकरण करना हैं।

१. डिप्थीरिया।
२. काली खांसी (काली खांसी)।
३. टेटनस।
४. क्षय रोग।
५. पोलियो।
६. हेपेटाइटिस बी।
७. खसरा।

इसके अलावा, इस अभियान के अंतर्गत चयनित राज्यों में जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (एचआईबी) के लिए भी टीके प्रदान किये जाएगें।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना के उद्देश्य से २० नवंबर, २०१४ को प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत कृषि और गैर-कृषि फीडर सुविधाओं को अलग-अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उप-पारेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा। योजना के अंतर्गत दोनों घटकों की कुल अनुमानित लागत ४३,०३३ करोड़ रूपये है जिसमें पूरे क्रियान्वयन अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा ३३,४५३ करोड़ रूपये की बजट सहायता भी शामिल है। यह योजना बेहद सफल योजना मानी गयी है।

दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने १६ अक्टूबर २०१४ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए श्रम की जरूरत है। हमने आज तक श्रम को उचित दर्जा नहीं दिया है। हमें अब श्रमिकों के प्रति नजरिया बदलना होगा। हमारा श्रमिक श्रम योगी है। मोदी ने कहा कि सत्यमेव जयते जितनी ही ताकत श्रमेव जयते में भी है।

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को सही ढंग से जलापूर्ति हो, उचित पर्यावरणीय माहौल मिले। पर्यावरण एवं जरुरत के अनुरूप विकास हो।

स्मार्ट सिटी

देश के हर परिवार को अपना घर और बेहतरीन जीवनशैली मुहैया करवाने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने २५ जून २०१५ को स्मार्ट सिटी समेत तीन बड़ी योजनाओं को लॉन्च किया। मोदी ने पुनरोद्धार एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और सभी के लिए आवास मिशन की शुरूआत की। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देशभर में १०० स्मार्ट शहर बसाने की योजना है। वहीं एएमआरयूटी योजना के तहत देश के ५०० शहरों का कायाकल्प किया जाएगा। ये शहर हाइटेक सुविधाओं से लैस होंगे। आवास योजना के तहत २०२२ तक देश के तमाम परिवारों को घर मुहैया करवाया जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना में सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को है। इस योजना के तहत यूपी में सबसे ज्यादा १३ स्मार्ट सिटी विकसित किये जाएंगे। इसके बाद तमिलनाडु में १२ और महाराष्ट्र में १० स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। १०० स्मार्ट सिटी पांच साल के भीतर विकसित किये जाएंगे और सभी के लिए आवास योजना के तहत अगले ७ साल में दो करोड़ मकानों का शहरी क्षेत्रों में निर्माण कराना है।

एफडीआई नियमों में सुधार

मोदी सरकार ने १० नवंबर २०१५ को एफडीआई नियमों को आसान करने का फैसला लिया, जिसमें एफडीआई प्रस्ताव की लिमिट को ३,००० करोड़ रुपये से बढ़ाकर ५,००० करोड़ रुपये कर दिया गया। अब ५,००० करोड़ रुपये तक के एफडीआई प्रस्तावों को एफआईपीबी की मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। साथ ही जहां एफडीआई पहले से १०० फीसदी तक है वहां नियमों को और आसान किया जाएगा। मंजूरी की प्रक्रिया तेज की जाएगी और कुछ सेक्टरों में ऑटोमेटिक अप्रूवल का दायरा

बढ़ाया जाएगा। सभी एफडीआई नियमों की एक किताब बनेगी। सरकार ने डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग, प्राइवेट बैंकिंग, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, माइनिंग, सिविल एविएशन, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, सिंगल ब्रांड रिटेल, कैश एंड कैरी होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग समेत १५ सेक्टरों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दी है।

सरकार ने ड्यूटी फ्री शॉपिंग पर एफडीआई के नियमों में भी ढील दी है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ५ साल के भीतर एफडीआई लाने की शर्त हटा ली गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ५ साल के बाद भी एफडीआई लाना मुमकिन होगा। एनआरआई निवेश में भी एफडीआई नियम आसान कर दिए गए हैं। डिफेंस सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के जरिए ४९ फीसदी के एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है। ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के तहत गैर-खबरिया चैनल में ऑटोमैटिक रूट के जरिए १०० फीसदी एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है। वहीं ब्रॉडकास्ट सेक्टर में एफआईपीबी के जरिए ४९ फीसदी एफडीआई निवेशक की छूट का ऐलान किया गया है।

एफएम रेडियो और न्यूज चैनल में ४९ फीसदी एफडीआई पर एफआईपीबी की मंजूरी जरूरी होगी। डीटीएच और केबल नेटवर्क में १०० फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है। रबर और कॉफी सेक्टर में १०० फीसदी एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है। एयरलाइंस ग्राउंड हैंडलिंग में १०० फीसदी एफआईडी को मंजूरी दी गई है। रीजनल एयरलाइंस में ४९ फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है। एनआरआई निवेश में भी एफडीआई नियम आसान किए गये हैं।

उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यिक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को अपनी अनुमति दे दी गयी है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को ५ करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए १६०० रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योग्य बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श द्वारा की जाएगी। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष २०१६-१७,२०१७-१८ और २०१८-१९ में किया जाएगा।

देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निर्धनतम परिवारों की करोड़ो महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजना का कार्यान्वयन करेगा।

देश में निर्धनों की अभी तक खाने पकाने की गैस (एलपीजी) तक सीमित पहुंच रही है। एलपीजी सिलेंडर की पहुंच मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक है और इनमें से भी औसतन परिवार मध्यम और समृद्ध वर्ग के हैं। जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना बनाने से स्वास्थ्य से जुडी गंभीर समस्याएं देखी गयी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक भारत में ५ लाख लोगों की मृत्यु अस्वच्छ जीवाश्म ईंधन के कारण होती है। इनमें से अधिकतर की मृत्यु का कारण गैरसंचारी रोग जैसे हृदय रोग, आघात, दीर्घकालीन प्रतिरोधी फेफडे संबंधी रोग और फेफडे का कैंसर शामिल है। घरेलू वायु प्रदूषण बच्चो को होने वाले तीव्र श्वास संबंधी रोगो के लिए बडी संख्या में जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई में खुली आग जलाना प्रति घंटे चार सौ सिगरेट जलाने के समान है।

बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश में खाने पकाने की गैस की पहुंच सभी लोगों तक संभव होगी। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी।

इससे खाने बनाने में लगने वाले समय और कठिन परिश्रम को कम करने भी सहायता मिलेगी। योजना से खाने पकाने की गैस के वितरण में कार्यरत ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा।

इस दिशा में वित्त मंत्री ने २९.०२.१०१६ को बजट भाषण में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की १.५ करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए २००० हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। इसके साथ ही बजट में ५ करोड़ परिवारों तक योजना का लाभ पंहुचाने के लिए योजना को दो ओर वर्ष तक लागू की घोषणा भी की गई। उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने हाल ही में बलिया उत्तर प्रदेश से की है।

अन्य योजनायें

- पिल्ग्रिमेज रेजुवेनशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्मेंटशन ड्राइव (प्रसाद योजना)
- नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटशन योजना (हृदय योजना)
- उड़ान स्कीम

- ३१–नेशनल बाल स्वच्छता मिशन
- वन रैंक वन पेंशन (OROP) स्कीम
- स्मार्ट सिटी मिशन
- गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम
- स्टार्टअप इंडिया, स्टन्डप इंडिया
- डिजिलोकर
- इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन
- सागरमाला प्रोजेक्ट
- 'प्रकाश पथ'– 'वे टू लाइट'
- उज्वल डिस्कॉम असुरन्स योजना
- विकल्प स्कीम
- नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- पहल डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर फॉर LPG (DBTL) कंस्यूमर्स स्कीम
- नेशनल इंस्टीटूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग)
- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
- नमामि गंगे प्रोजेक्ट
- सेतु भारतं प्रोजेक्ट
- रियल एस्टेट बिल
- आधार बिल
- क्लीन माय कोच
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

मेक इन इंडिया– विकास में सहायक

मेक इन इंडिया का मकसद देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को मूल रूप से एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है ताकि १२५ करोड़ की आबादी वाले मजबूत भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर पैदा हों। इससे एक गंभीर व्यापार में व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इसमें किसी नवाचार के लिए आवश्यक दो निहित तत्वों नये मार्ग या अवसरों का दोहन और सही संतुलन रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना शामिल हैं। राजनीतिक नेतृत्व के व्यापक रूप से लोकप्रिय होने की उम्मीद है। लेकिन 'मेक इन इंडिया' पहल वास्तव में आर्थिक विवेक, प्रशासनिक सुधार के न्यायसंगत मिश्रण के रूप में देखी जाती है। इस प्रकार यह पहल जनता जनादेश के आह्वान– 'एक आकांक्षी भारत' का समर्थन करती है।

प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य

- मध्यावधि की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में १२–१४ प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि करने का लक्ष्य।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी २०२२ तक बढ़ाकर १६ से २५ प्रतिशत करना।

- विनिर्माण क्षेत्र में २०२२ तक १०० मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना।
- ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीब लोगों में समग्र विकास के लिए समुचित कौशल का निर्माण करना।
- घरेलू मूल्य संवर्द्धन और विनिर्माण में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना।
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना।
- भारतीय विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना।

सकारात्मक बातें

- भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी हाजिरी दर्ज करा चुका है।
- यह देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला है और उम्मीद की जाती है कि वर्ष २०२० तक यह दुनिया की सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा।
- अगले दो तीन दशकों तक यहां की जनसंख्या वृद्धि उद्योगों के अनुकूल रहेगी। जनशक्ति काम करने के लिए बराबर उपलब्ध रहेगी।
- अन्य देशों के मुकाबले यहां जनशक्ति पर कम लागत आती है।
- यहां के व्यावसायिक घराने उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से, भरोसेमंद तरीकों से और व्यावसायिक रूप से काम करते हैं।
- घरेलू मार्किट में यहां तगड़ा उपभोक्तावाद चल रहा है।
- इस देश में तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताएं मौजूद है और उनके पीछे वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों का हाथ है।
- विदेशी निवेशकों के लिए बाजार खुला हुआ है और यह काफी अच्छी तरह से विनियमित है।

जनशक्ति प्रशिक्षण

कोई भी उत्पादन क्षेत्र बिना कुशल जनशक्ति के सफल नहीं हो सकता। इसी सिलसिले में यह संतोषजनक बात है कि सरकार ने कौशल विकास के लिए नये उपाय किये हैं। इनमें से निश्चय ही गांवों से रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन रुकेगा और शहरी गरीबों का अधिक समावेशी विकास हो सकेगा। यह उत्पादन क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

नये मंत्रालय– कौशल विकास और उद्यमियता ने राष्ट्रीय कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन शुरू कर दिया है। ये ध्यान देने की बात है कि मोदी सरकार ने ग्राम विकास मंत्रालय के तहत एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम का नाम बीजेपी के नायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। नये प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर

में १५०० से २००० तक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का कार्यक्रम है। इस सारी परियोजना पर २००० करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। यहां सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रारूप में संचालित की जाएगी।

नये प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत युवा वर्ग को उन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनकी विदेशों में मांग है। जिन देशों को नजर में रखकर यह कार्यक्रम बनाया गया है, उनमें स्पेन, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और पश्चिम एशिया शामिल हैं। सरकार ने हर साल लगभग तीन लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव किया है और इस प्रकार से वर्ष २०१७ के आखिर तक १० लाख ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

अन्य जो उपाय किये जाने हैं उनमें मूल सुविधाओं और खासतौर से सड़कों और बिजली का विकास करना शामिल है। लंबे समय तक बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सॉटवेयर कंपनियां भारत में इसलिये काम करना पसंद करती थी, क्योंकि यहां एक विस्तृत मार्किट और नागरिकों की खरीद क्षमता है। इसके अलावा इस देश में उत्पादन सुविधायें भी मौजूद हैं। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यहां पर सशक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति, नौकरशाहों और उद्यमियों का अनुकूल रवैया, कुशल जनशक्ति और मित्रतापूर्ण निवेश नीतियां मौजूद हैं।

इसी संदर्भ में सरकार की दिल्ली और मुम्बई के बीच एक औद्योगिक गलियारा विकसित करने की कोशिशों की जा रहीं हैं। सरकार बहुपक्षीय नीतियों पर काम कर रही है। इनमें मुख्य संयंत्रों और मूल सुविधाओं के विकास में सम्पर्क स्थापित करने और पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने, उच्च क्षमता की परिवहन सुविधा विकसित करने का काम शामिल है। इन क्षेत्रों में काम करते हुए सरकार ने पांच सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के ११ निगम ऐसे हैं, जिनके बारे में सरकार का विचार है कि छः निगमों को बंद कर दिये जाने की जरूरत है। १००० करोड़ रूपये की लागत पर इन निगमों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई जा रही है। यह एक बारगी समझौता होगा।

सरकार द्वारा संचालित जिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को फिर से काम लायक बनाने का फैसला किया गया है। उनमें एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, नेपा लिमिटेड, नगालैंड पेपर एंड पल्प कंपनी लिमिटेड और त्रिवेणी स्ट्रेक्चरल्स शामिल हैं।

उर्जा क्षेत्रः विद्युतीकरण क्षेत्र में परिवर्तनकारी कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता सम्हालने के बाद ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। कार्य प्रगति की रफ्तार तेज हुई और पारदर्शिता को बल मिला है। मोदी ने इस कार्य को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हुए अपना एजेंडा स्पष्ट किया था, जिसे पूरा करने की दिशा में वे और उनकी सरकार सतत गतिशील हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण की दिशा में पारदर्शी ढंग से काम करते हुए मई २०१८ तक १८००० उन गांवों हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया गया है जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँच सकी है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विद्युतीकरण

के कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए एक वेब पोर्टल (http://garv.gov.in/) एवं 'GARV' नाम से एक मोबाइल एप जारी किया गया है। इस वेब-पोर्टल अथवा मोबाइल एप से कोई भी व्यक्ति राज्यवार, जिलेवार, पंचायतवार सहजता से यह विवरण प्राप्त कर सकता है कि किसी क्षेत्र-विशेष विद्युतीकरण का कार्य कितना हुआ है, अथवा कितना शेष बचा है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से न सिर्फ कार्य का ब्यौरा प्राप्त किया जा सकता है बल्कि कार्य-प्रगति संबंधी समस्त जानकारी भी हासिल की जा सकती है। इस माध्यम में कार्य की प्रगति से जुड़े अधिकारी से संबंधित सम्पर्क जानकारी भी सार्वजनिक की गयी है। चूँकि सार्वजनिक स्तर पर विद्युतीकरण से जुडी योजनाओं के सार्वजनिक होने की वजह से लापरवाही आदि की संभवाना बहुत कम रहती है और कार्य से जुड़े पड़ताल की जानकारी हासिल करना बेहद आसान होता है। अगर कहीं से कोई गलत जानकारी सरकार को किसी निचले स्तर के अधिकारी द्वारा दी जाती है तो उस जानकारी को क्रॉस-चेक करना किसी के लिए भी बेहद आसान हो गया है।

पीआईबी पर उपलब्ध ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल २०१६ तक ७,४४५ गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। विद्युत मंत्रालय की वेबसाईट के अनुसार बिजली की उत्पादन क्षमता में २२,५०६ मेगावाट की बढ़ोत्तरी हुई है तो वहीं ६५,५५४ मेगा वोल्ट एमप. की बढ़ोत्तरी सब-स्टेशन की संख्या में हुई है। २२,१०० सर्किट किलोमीटर विद्युत लाइनों पर काम पूरा हो चुका है। हालांकि ई-शासन के तहत विद्युतीकरण से जुड़े कार्यों में अलग-अलग स्तर पर अलग वेब-पोर्टल्स उपलब्ध हैं, जहाँ से संबंधित जानकारियों को सहजता से हासिल किया जा सकता है। विद्युतीकरण एवं ऊर्जा क्षेत्र को ई-शासन के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में चल रहे कुछ वेब पोर्टल्स निम्न हैं:

१. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना- http://www.ddugjy.gov.in/

२. उज्ज्वल भारत- http://ujwalbharat.gov.in/

३. विद्युत मंत्रालय- http://powermin.nic.in/hi

४. विद्युत प्रवाह- http://www.vidyutpravah.in/

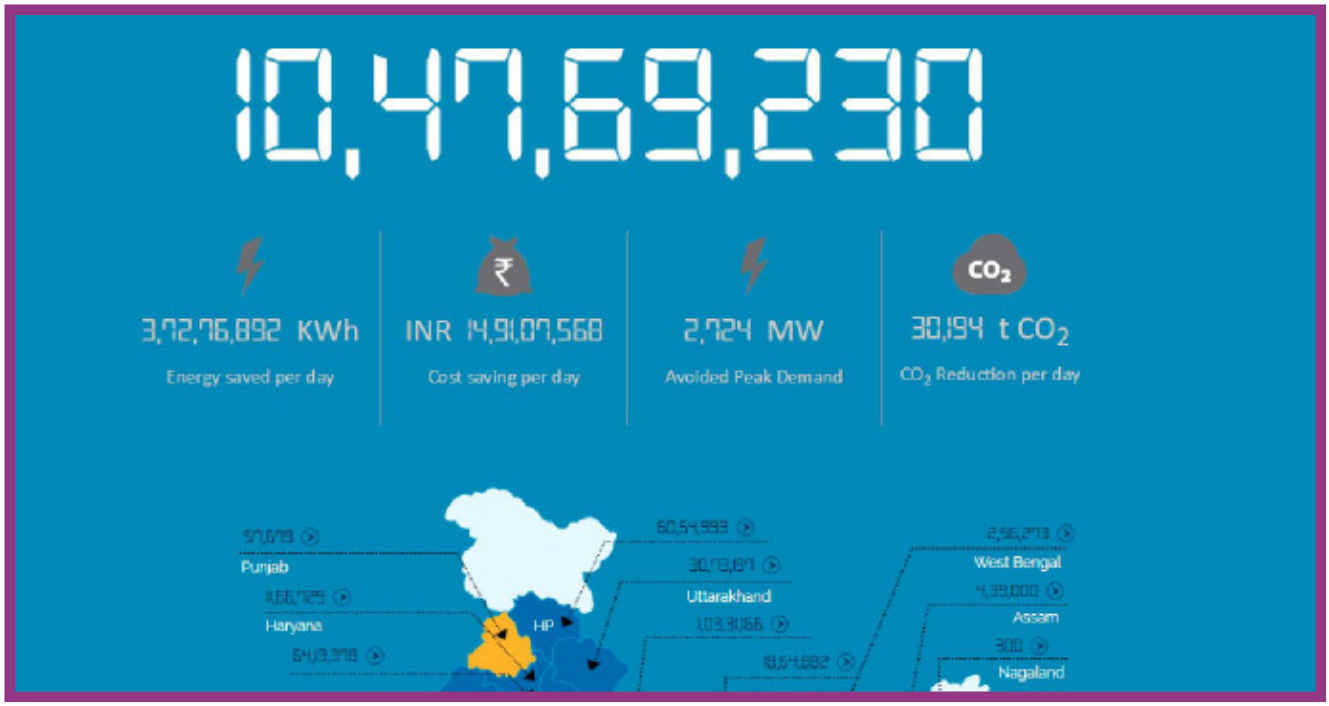

हालांकि ऊर्जा क्षेत्र में बिजली बचाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एलईडी को बढ़ावा देने की दिशा में काफी प्रयास किये हैं, जिन्हें व्यापक सफलता मिली है। जब प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी तब लक्ष्य रखा गया था कि मार्च, २०१५ से एलईडी बल्बों को चरणबद्ध तरीके से वितरित किया जाएगा एवं मार्च, २०१६ तक १०० शहरों में घरों और सड़कों पर एलईडी बल्ब लगाए जाने की परियोजना पूरी कर ली जाए। इस कार्य हेतु प्रधानमंत्री ने घरेलू बिजली बचत योजना (डीईएलपी) के तहत दिल्ली के उपभोक्ताओं द्वारा एलईडी बल्ब प्राप्त करने के आवेदनों के पंजीकरण के लिए एक वेब-आधारित प्रणाली की शुरूआत की। उपभोक्ता वेबसाइट www.eeslindia.org/Delhi-Launch पर या निर्धारित नम्बर पर एसएमएस भेजकर पंजीकरण कर सकते हैं। श्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले पंजीकरण कराने वाले दिल्ली के एक आम नागरिक को दो एलईडी बल्ब प्रदान किया था। वर्तमान में http://www.ujala.gov.in/ के अनुसार १०,४७,६६,२५ बल्ब लगाये जा चुके हैं। इससे ३,७२,७६,८६२ KWh बिजली प्रति दिन बचाई जा रही है जबकि १४,६१,०७,५४८ रूपये की बचत भी हो रही है।

जनता के सरकार के बीच कम हुआ फासला

मोदी सरकार आने के बाद जनता और सरकार के बीच संवाद की संभावना तेजी से बढ़ी है। यह सरकार संवाद और हिस्सेदारी की पक्षधर है। सबको साथ लेकर विकास की रफ्तार को बढाने का काम अभूतपूर्व ढंग से भाजपा-नीत केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। लोक और तंत्र के बीच संवाद का सुगम होना लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बड़ा कारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के तहत 'Write To PM' विकल्प के जरिये जनसंवाद का एक अभूतपूर्व मंच उपलब्ध कराया है। भारत जैसे एक विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए यह प्रधानमंत्री से संवाद का यह ऑनलाइन विकल्प अभूतपूर्व इस लिहाज से भी कहा जा सकता है क्योंकि भारत के आमजन की अवधारणा में यह कल्पना की भी बात नहीं थी कि वे प्रधानमंत्री को सीधा पत्र लिखेंगे और उसपर त्वरित कार्रवाई होगी। इसके लिए बाकायदे एक वेब माध्यम (http://pmindia.gov.in/en/interact-with-honble-pm/) तैयार किया गया है। इस वेब माध्यम से कोई भी आम अथवा खास व्यक्ति प्रधानमंत्री को समस्या, शिकायत अथवा सुझाव से जुड़े पत्र लिख सकता है। इस पत्र को लिखते ही प्रेषक को एक पंजीकरण नम्बर प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑनलाइन प्राप्त होता है। उस पंजीकरण नम्बर के माध्यम से पत्र लिखने वाला व्यक्ति द्वारा http://pgportal.gov.in/viewstatus.aspx पर जाकर अपने शिकायत, सुझाव अथवा समस्या पर हुई कार्रवाई अथवा प्रगति की सटीक एवं आधिकारिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस माध्यम की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध है एवं वहीं से पत्र के विषय से जुड़े विभागों एवं मंत्रालयों को हस्तांतरित की जाती है। पत्र प्रेषक को उक्त अधिकारी का संपर्क सूत्र भी उपलब्ध कराया जाता है जिसके अधीन उसका मामला है। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री से संवाद का यह विकल्प उस अवधारणा को खंडित करने में मदद कर रहा है, जिसमे आम लोग अक्सर यह मान लेते थे कि उनकी सुनवाई प्रधानमंत्री तक संभव ही नहीं है। इस ऑनलाइन माध्यम की गंभीरता और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनेक बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रों का जिक्र किया है जो उन्हें इस ऑनलाइन माध्यम से लिखे गये हैं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से स्थापित नवोन्मेषी प्रणाली ने कहीं कहीं पारदर्शिता के साथ शासकीय व्यवस्था में जनसंवाद की संभावना को मजबूत करने का काम किया है। हालांकि इसके अतिरिक्त 'नरेंद्र मोदी' मोबाइल एप के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जनता से संवाद को प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों में भी जन-भागीदारी को तरजीह दी जा रही है। रेल मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया फीडबैक सिस्टम पर खास जोर दिए जाने से सुधारों को नई दिशा मिलती दिख रही है एवं जनता में भी आत्म विश्वास बढ़ता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटाईजेशन को बढ़ावा देते हुए इसे जनता से संवाद के सबसे कारगर उपकरण के तौर पर स्वीकार किया है।

JAM: जनधन, आधार, मोबाइल योजना

JAM का विजन, आगामी कई पहलों के लिए बुनियाद का काम करेगा। मेरे लिए JAM का मतलब है अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति। खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का अधिकतम प्रतिफल। हमारे गरीबों का अधिकतम सशक्तिकरण। जनता के बीच तकनीक का अधिकतम प्रसार।

– नरेंद्र मोदी

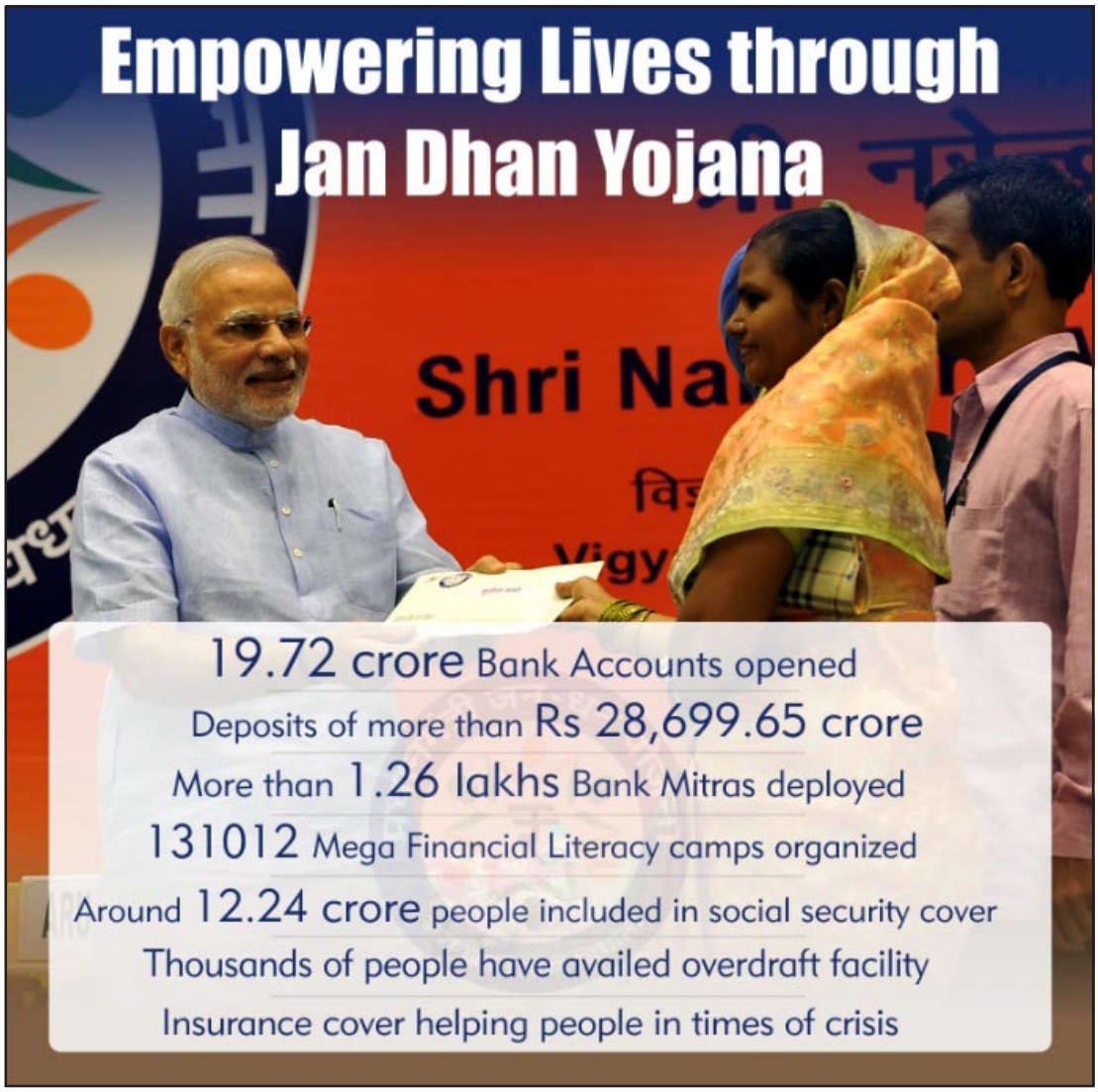

आजादी के ६७ साल बाद भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जिन्हें बैंकिंग सेवाएं नहीं हासिल थीं। इसका मतलब है कि उनके पास न तो बचत कोई जरिया था, न ही संस्थागत

कर्ज पाने का कोई अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बुनियादी मसले का समाधान करने के लिए २८ अगस्त को जन धन योजना की शुरुआत की। कुछ ही महीनों के भीतर इस योजना ने लाखों भारतीयों के जीवन और भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। महज एक साल में १९.७२ करोड़ बैंक खाते खोले गए। अभी तक १६.८ करोड़ रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में २८,६९९.६५ करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। रिकॉर्ड १,२५,६९७ बैंक मित्रों को तैनात किया गया। इसने एक सप्ताह में सबसे अधिक १,८०,९६,१३० बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि लाखों बैंक खातों को खोलना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती लोगों की आदत में बदलाव लाना था, ताकि वो बैंक खातों का इस्तेमाल शुरू करें। जीरो बैलेंस खातों की संख्या सितंबर २०१४ में ७६.८ प्रतिशत से घटकर दिसंबर २०१५ में ३२.४ प्रतिशत रह गई। ओवरड्राट के रूप में अभी तक १३१ करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग किया गया। ये सब प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा तथा जनता और सरकारी मशीनरी को प्रोत्साहित करने की उनकी शक्ति द्वारा संभव हुआ।

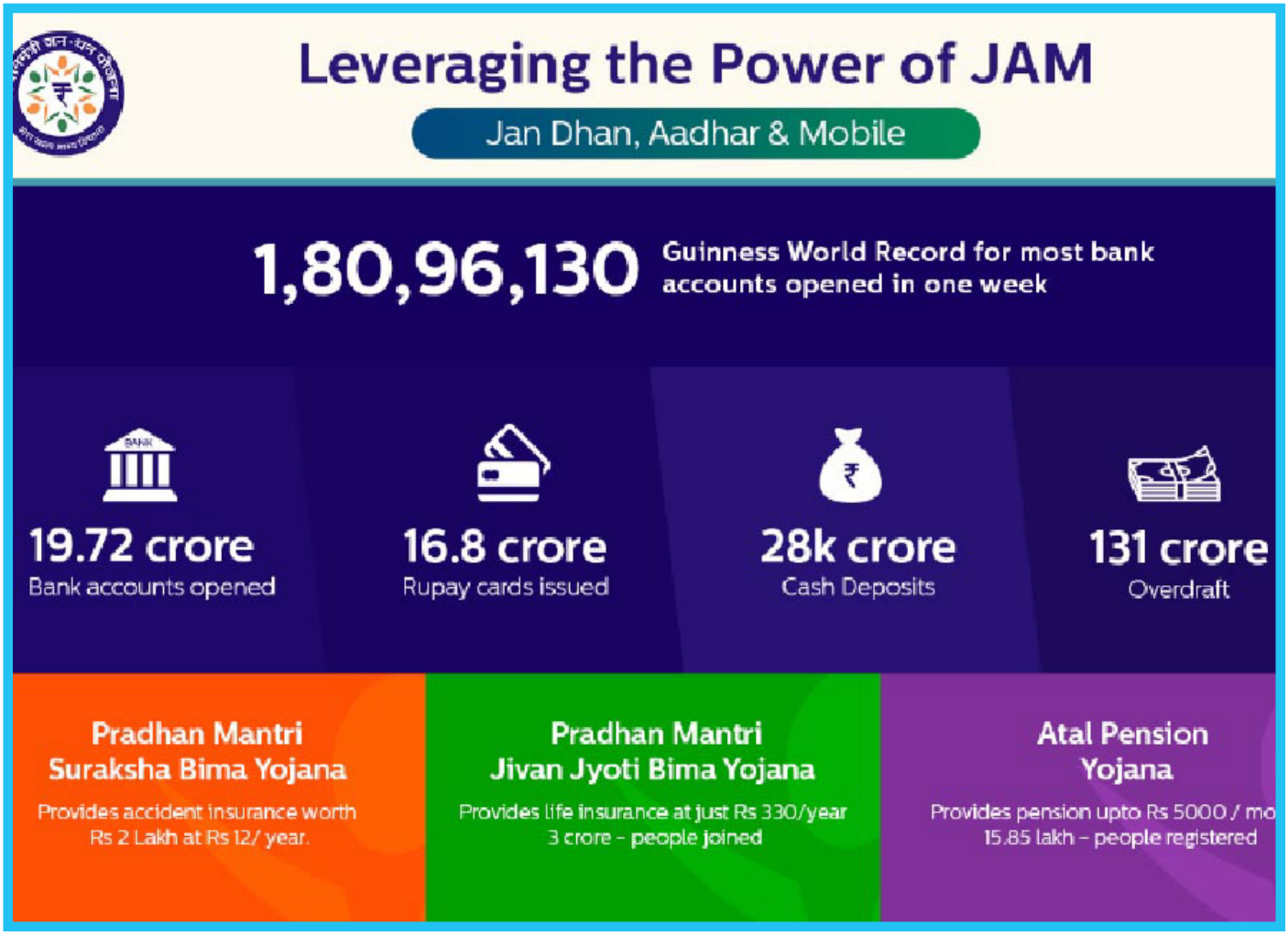

इस विशाल कार्य को मिशन मोड़ में लिया गया और सरकार तथा जनता की साझेदारी और भागीदारी में पूरा किया गया, जो अनुकरणीय है। लाखों भारतीयों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए बैंक खाते दिए गए, साथ ही इस पहल ने भ्रष्टाचार को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। अब डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर्स के रूप में सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराई जा सकती है। इससे लीकेज और किसी हेराफेरी की गुंजाइश खत्म हुई है। पहल योजना ने हाल में दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। पहल योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराई जाती है। इस योजना के तहत १४.६२ करोड़ से अधिक लोगों को सीधे नकद सब्सिडी मिल रही है। इस योजना ने करीब ३.३४ करोड़ नकली या निष्क्रिय खातों की पहचान करने और उन्हें बंद करने में भी मदद की, जिससे हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई। इस समय सरकार करीब ३५-४० योजनाओं के लिए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर्स का उपयोग कर रही है और २०१५ में करीब ४०,००० करोड़ रुपये लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित किए गए। आम लोगों के लिए बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ ही एनडीए सरकार ने नागरिकों को बीमा और पेंशन कवर देने के लिए ऐतिहासिक कदम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रति वर्ष महज १२ रुपये में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मुहैया कराती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रतिवर्ष ३३० रुपये में जीवन बीमा उपलब्ध कराती है। अटल पेंशन योजना अंशदान के आधार पर ५००० रुपये प्रति माह तक पेंशन उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ६.२ करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और करीब ३ करोड़ लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल हुए हैं। अटल पेंशन योजना के लिए करीब १५.८५ लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। ❍

स्रोतः http://www.narendramodi.in/

एलपीजी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के समक्ष आने वाली शुरुआती समस्या के बाद वर्तमान एनडीए सरकार ने इसे नये सिरे से 'पहल' नामक योजना के तहत शुरू किया। देश के ५४ जिलों में १५ नवंबर २०१४ से और फिर पूरे देश में एक जनवरी २०१५ से इसे लागू कर दिया गया।

एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, 'पहल योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स ने दुनिया की सबसे बड़ी नकदी अंतरण योजना के तौर पर माना है। योजना के तहत ३० जून २०१५ की स्थिति के अनुसार देश के १२.५७ करोड़ परिवारों को सीधे सब्सिडी अंतरण उनके खातों में किया जा रहा है।'

वक्तव्य के अनुसार, '३ दिसंबर २०१५ की स्थिति के अनुसार १४.६२ करोड़ एलपीजी उपभोक्ता पहल योजना में शामिल हुए हैं और उन्हें गैस सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है।'

स्रोतः जी मीडिया

खादी कुटीर उद्योग : सरकार, बाजार और रोजगार

केंद्र सरकार के दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। ग्रामीण विकास एवं ग्रामोद्योग को लेकर भी मोदी सरकार शुरुआत से ही गंभीर रही है। गांधी के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिए चल रही सरकार ने गांधी के खादी अवधारणा को काफी प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। ग्रामोद्योग एवं खादी पर चल रहे सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन जरुरी है।

खादी वस्त्र नही विचार है! यह उक्ति खादी के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रचलित रही है। इस उक्ति में दो शब्द प्रमुखता से एवं व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। ये दो शब्द हैं वस्त्र एवं विचार। वर्तमान समाजिक परिप्रेक्ष्य में इन दोनों ही शब्दों की व्यापक सन्दर्भों में व्याख्या की जा सकती है। चूंकि वस्त्र मानव की भौतिक जरूरत है तो वहीं विचार उसकी समाजिकता का मूल है। उसके विचार ही उसकी समाजिक पहचान को स्थापित करते हैं। ऐसे में विचार के स्तर पर खादी की अवधारणा समाज में जितनी मजबूती से स्थापित होगी, समाज में स्वदेशी भावना का विकास भी उतनी ही मजबूती से होगा। आज के संदर्भ में खादी का दायरा महज वस्त्र अर्थात तन ढकने के वाले एक लिबास तक सीमित है, ऐसा कहना गलत प्रतीत होता है। उपयोग के स्तर पर देखा जाय तो खादी हमारे समाजिक परिवेश में घरेलू स्तर की तमाम जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक सम्भावित उद्योग है। मसलन, सूत से निर्मित कपड़ा, फलों से बने पेय उत्पाद, माचिस, चमड़ा उत्पाद, मिट्टी के वर्तन, हस्तकला के नमूने इत्यादि। उपभोग की प्रवृति से इतर अगर उपयोग के स्तर पर खादी का मूल्यांकन करें तो खादी के क्षेत्र में ऐसी तमाम सम्भावनाएं नजर आयेंगी जो लघु अर्थात कुटीर उद्योग के रूप में खादी को एक बेहतर विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकती हैं। इसमें बाजार की सम्भावना है तो रोजगार की भी भरपूर गुंजाइश है। खादी ग्रामीण कुटीर उद्योग का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके स्थापन के लिए पूँजी की कोई आवश्यकता नहीं होती अथवा बेहद कम आवश्यकता होती है जो इसकी ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार के अत्यंत व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापना करती है। अगर देखा जाय तो इसके अलावा बड़ी बात ये भी है कि खादी के विकास में ही ग्रामीण समाज के स्वालम्बन की संभावना भी निहित है। अब बड़ा सवाल ये है कि खादी के क्षेत्र में कुटीर-उद्योग से रोजगार सृजन एवं ग्रामीण समाज में स्वालम्बन आदि उपर्युक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किन उपायों पर अमल किया जाना चाहिए एवं इस दिशा किन-किन स्तरों पर कार्य चल रहे हैं? इस संदर्भ में इस बात पर भी गौर किया जाना जरुरी है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किन पक्षों पर खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है? मूलतया जब बात रोजगार सृजन और उद्ययोग स्थापन की हो तो सरकार एवं बाजार दोनों का ही दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। खादी के क्षेत्र में कुटीर उद्योगों की बात करते समय सरकार के प्रयासों एवं बाजार

की संभावना को को चर्चा के केंद्र में लाना ही होगा। चूंकि रोजगार बाजार आश्रित होता है जबकि बाजार की निर्भरता उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र पर होती है। वहीं उत्पाद अथवा सेवा क्षेत्र के लिए कौशल का होना पहली जरूरत है लिहाजा यह कहा जा सकता है कि उत्पादन अथवा सेवा क्षेत्र कौशल पर निर्भर है। अतः व्यवहारिक तौर पर एक बात स्पष्ट है बाजार, उत्पादन और कौशल के बीच परस्पर निर्भरता की स्थिति है। इस दिशा में पहला दायित्व सरकार का आता है कि वो खादी क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों के विस्तार की दिशा में क्या प्रयास कर रही है।

खादी क्षेत्र में सरकार के प्रयास

खादी उद्योग के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रयास रहे हैं। वर्तमान की केन्द्रीय योजनाओं की बात करें तो इनमे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ब्याज अनुवृत्ति पात्रता प्रमाणपत्र योजना आदि प्रमुख हैं। 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) का प्रमुख उद्देश्य सभी तरह के ग्रामोद्योगों जिनमे कुटीर खादी ग्रामोद्योग भी आते हैं, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें स्थापित करवाना है। केंद्र सरकार ने डिजिटल माध्यमों से इस योजना को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बेहतर प्रयास किया है। इसके तहत व्यक्ति को परियोजना की कुल लागत का १० प्रतिशत पहले स्वयं निवेश करना होता है, इसके बाद शेष ९० प्रतिशत की सहायता ऋण के रूप में भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत चिन्हित बैंकों में से किसी के द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना का प्रमुख रूप से संचालन खादी ग्रोमोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। इसके बाद ब्याज अनुवृत्ति पात्रता प्रमाणपत्र योजना की बात करें तो यह समग्र खादी उद्योग के लिए धन का प्रमुख स्रोत है। इसका आरम्भ सन १९७७ में तब किया गया जब खादी ग्रोमोद्योग के लिए निर्धारित बजट के तहत प्राप्त धन और व्यय के बीच अंतर बढ़ने लगा। इसके तहत बैंक द्वारा व्यक्ति को उसकी कार्यात्मक राशि की पूर्ती हेतु ४ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायती दर से ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना की सबस बड़ी विशेषता यह है कि ये खादी से सम्बंधित उद्योगों के लिए ही ऋण प्रदान करती है। खादी निर्माण करने वाले व्यक्ति ही इस योजना के तहत ऋण पाने के अधिकारी होते हैं। खादी ग्रामोद्योग से सम्बंधित इन केन्द्रीय योजनाओं के अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी खादी को लेकर तमाम योजनाएं व कार्यक्रम संचालित हैं। इस संदर्भ में देश के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उल्लेख करें तो इन दोनों राज्यों में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार की उपर्युक्त योजनाओं के साथ-साथ राज्य स्तर पर क्रमशः मुख्यमंत्री ग्रोमोद्योग रोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना आदि का भी संचालन किया जा रहा है। इसी तरह से देश के लगभग हर राज्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मौजूद है जिसके तहत उस राज्य की खादी ग्रामोद्योग से सम्बंधित योजनाओं का क्रियान्वयन आदि हो रहा है।

उपर्युक्त सरकारी योजनाए खादी ग्रामोद्योग के स्थापन के लिए ऋण व अनुदान के जरिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर केन्द्रित हैं। पर सिर्फ धन के निवेश से यह ग्रोमोद्योग स्थापित हो जाएंगे, यह नहीं कहा जा सकता। दरअसल किसी भी उद्योग के लगने के बाद उसके चलने के लिए दो चीजों की क्रमशः आवश्यकता होती है- पहली, कुशल कारीगरों की

और दूसरी, उत्पादित माल के लिए लाभकारी बाजार की। इन दोनों चीजों की दिशा में सरकार क्या कर रही है और इनमे क्या समस्याएँ हैं, यह समझना भी बेहद जरुरी है।

कुटीर खादी ग्रामोद्योग के लिए कौशल प्रशिक्षण

कुटीर खादी ग्रोमोद्योग जिसके अंतर्गत कपड़े से लेकर माचिस बनाने तक का काम होता है, के लिए कुशल कामगार तैयार करने की दिशा में भी केंद्र व राज्य स्तर पर कुछ योजनाए अवश्य संचालित हैं। कौशल प्रशिक्षण से सम्बंधित ऐसी ही कुछ योजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैः

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी): यह सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके तहत लघु उद्योगों जिनके अंतर्गत कुटीर खादी ग्रामोद्योग भी आता है, से सबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों से युवाओं को अवगत कराने व इस दिशा में उनके कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से देश भर उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनका आयोजन प्रायः आईटीआई आदि तकनिकी संस्थानों में किया जाता है, क्योंकि इन संस्थानों के शिक्षकों-छात्रों में नए लोगों को प्रेरित करने वाला उद्यमिता कौशल उपलब्ध होता है।

उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी): इस कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म उद्योगों से सम्बद्ध उद्यमियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए व्यापक और वृहद् स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम लगभग ६० विधाओं में प्रशिक्षण कार्य करता है।

व्यवसाय कौशल विकास कार्यक्रम (बीएसडीपी): यह कौशल विकास उन नए सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के उद्यमियों के लिए है, जिनमे व्यावसायिक समझ का अभाव है। उनमे व्यावसायिक समझ का विकास करने के लिए बिजनेस कौशल विकास नामक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

इनके अतिरिक्त कौशल विकास से सम्बद्ध और भी कई योजनाएं व कार्यक्रम केंद्र तथा राज्य स्तर पर संचालित हैं। हालांकि अभी हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा अपने अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्किल इंडिया का आरम्भ किया गया। लेकिन इसमें खादी ग्रामोद्योग को लेकर सीधे तौर पर कोई विशेष प्रावधान नहीं दिखता, जबकि उचित होता कि कुटीर खादी ग्रामोद्योग को विशेष रूप से स्किल इण्डिया के तहत लाया जाता। खादी ग्रामोद्योग कौशल प्रशिक्षण से सम्बंधित सभी छोटी-बड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों को स्किल इण्डिया के तहत लाया जाता जिससे उन्हें एक राष्ट्रीय स्वरुप मिल पाता। इससे दो फायदे होतेय पहला कि लोगों में खादी ग्रामोद्योग के कौशल विकास को लेकर और जागरूकता आती तथा स्किल इण्डिया के तहत आ जाने से इस सम्बन्ध में प्रशासनिक स्तर पर और भी गंभीर ढंग से प्रयास होते।

खादी कुटीर ग्रामोद्योग के लिए बाजार सृजन

कुशल कारीगर तैयार करने तथा उद्योग स्थापन और उत्पादन आरम्भ हो जाने के बाद प्रश्न यह आता है कि उद्यमियों को बाजार कैसा मिल रहा है? क्योंकि सहज और लाभकारी बाजार की अनुपलब्धता होने की स्थिति में खादी ग्रामोद्योग हो या अन्य कोई भी उद्योग, उसका

अधिक समय तक बने रहना मुश्किल है। लिहाजा देखना होगा कि सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में क्या कर रही है? इस दिशा में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा खादी ग्रामीण उद्योग आयोग को खादी ग्रामोद्योग के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद के रूप में मानद दर्जा दिया गया है। इस रूप में आयोग के कार्य ब्रैंड प्रोत्साहन, उत्पाद विकास, विभागीय बिक्री केंद्रों की सुव्यवस्था, सरकारी आपूर्तियों और निर्यात के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है। इसके अतिरक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और क्रय-विक्रय मेलों में सहभागिता के द्वारा निर्यात बाजार को प्रोत्साहन देना तथा खादी ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के जरिए निर्यात बाजार को प्रोत्साहित करना भी आयोग के कार्यों में शामिल है। अब चूंकि ये प्रयास अधिकाधिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की भागेदारी बढ़ाने को लेकर हैं, ये उद्यमियों के लिए एक अप्रत्यक्ष बाजार हो जाता है। लिहाजा सरकार को यह भी चाहिए कि वो खादी ग्रामोद्योग उद्यमियों के आसपास प्रत्यक्ष लाभकारी बाजार के निर्माण की दिशा में कोशिश करे। इससे न केवल इन उद्यमियों को अपने कार्य की सार्थकता व महत्व का अनुभव होगा, वरन अपने उत्पाद के लिए आसपास बाजार होने से उनका उत्साह भी बढ़ेगा जो कि इस खादी ग्रामोद्योग के उत्थान के लिए अत्यंत महत्वकारी होगा।

कुल मिलाकर उपर्युक्त सभी बातों को देखने के बाद देश में खादी ग्रामोद्योग के विषय में कहा जा सकता है कि इसके लिए सरकारी स्तर पर काफी प्रयास हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। खादी सिर्फ एक वस्तु या उद्योग साधन नहीं, ये तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पावन स्मृति तथा भारतीय ग्रामीण संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। अतः इसकी औद्योगिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान सरकार सतत आगे बढ़ती दिख रही है।

योग की बढ़ी अन्तरराष्ट्रीय साख

शिवानन्द द्विवेदी

ऐतिहासिक मानदंडों पर योग को देखें तो भारतीय परम्परा में योग विद्या की अवधारणा कोई आज की बात नहीं है। बल्कि भारत में वैदिक काल से ही योग विद्या को स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए जरुरी उपकरण के तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। इसमें को कोई शक नहीं कि हमारा इतिहास दर्शन इस बात की पुष्टि करता है कि प्राचीन काल से ही भारत अपने तमाम विद्याओं एवं पद्धतियों की वजह से विश्वगुरु के रूप में ख्यातिलब्ध रहा है। योग विद्या भी उन्हीं में से एक है। हालांकि समयचक्र के परिवर्तन एवं कालखंडों में हुए फेर ने ऐसे तमाम भारतीय परम्परागत जीवन पद्धति के उपकरणों को हाशिये पर लाकर छोड़ दिया, जो किसी जमाने में हमारे जीवन का अहम हिस्सा हुआ करते थे।

अभी पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रस्ताव को १७७

देशों के समर्थन से अनुमति दी थी, जिसमे मोदी ने योग को वैश्विक स्तर पर लाने और अमल करने की बात कही थी। गौरतलब है कि अपने अमेरिकी दौरे के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी २७ सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमे कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र योग को अन्तराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में लाने के लिए विचार करे। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर अमल करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने ३ महीने के भीतर ही २१ जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कर लिया। कहीं न कहीं इसे मोदी के मुहीम की सफलता के तौर पर एवं भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया। हाशिये पर पड़े इस वैदिक आरोग्य संस्कार के पद्धति को प्रधानमंत्री मोदी ने पुनः वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित किया है।

योग को स्वीकार करने वाले १७७ देशों में, उत्तरी अमेरिका के २३ देश, दक्षिणी अमेरिका के ११ देश, यूरोप के ४२ देश, एशिया के ४० देश, अफ्रीका के ४६ देश एवं अन्य १२ देश शामिल हैं। योग को अन्तराष्ट्रीय मान्यता के तौर पर स्थापित होने के साथ-साथ वैश्विक इतिहास में दो रोचक घटनाएं भी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र में यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ है कि पहली बार कोई प्रस्ताव इतने बड़े बहुमत और इतने कम समय में पारित हुआ है। इस रिकॉर्ड के मायने यहीं बयां करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव पर दुनिया वाकई गंभीर थी और उसी गंभीरता की परिणितिथी कि २१ जून को अन्तराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चिन्हित किया जा सका। हालांकि जब अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर जब पहला २१ जून नजदीक आ रहा है और दुनिया के १७७ देश अपनी स्वीकारोक्ति को अमली जामा पहनाने चुके थे, ऐसे में भारत उनके लिए योग का आदर्श देश बना। मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि भारतीय संस्कृति से चिढ रखने वाले कथित वामपंथी एवं सेकुलर मिजाज नेताओं को यह गौरव रास नहीं आया। इन कथित बुद्धिजीवियों एवं सेकुलरिज्म की राजनीति का दावा करने वाले राजनेताओं ने खुद को इससे अलग रखकर यह साबित किया है कि वे भारत की सांस्कृतिक विरासतों से कितना चिढ़ते हैं! सूर्य नमस्कार को लेकर हुए विरोध के बाद सरकार ने इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया। मगर सवाल ये है कि आखिर भारत में रहकर भारत की संस्कृति से ही चिढ़ रखने वालों को क्या कहा जाय? आखिर सूर्य कैसे साम्प्रदायिक हो गये, ये समझना असंभव लगता है। वैज्ञानिक तौर पर भी सूर्य प्रकाश ऊर्जा के स्त्रोत हैं एवं सूर्य से हर जाति, धर्म, देश को समान ऊर्जा मिलती है। लेकिन सेकुलरिज्म की आड़ में वैमनष्य का प्रपंच बो रहे लोगों को ये बात कभी समझ नहीं आती।

सेकुलरिज्म बनाम साम्प्रदायिकता की बहस में महत्वपूर्ण एवं अहम् मुद्दों का हाशिये पर जाना कोई नई बात नहीं है। विवाद के केंद्र में योग एवं सूर्य नमस्कार को ही खड़ा कर दिया गया जो आज भी प्रासंगिक हो उठता है। बहस ये है कि योग एवं सूर्य नमस्कार, साम्प्रदायिक है अथवा सेकुलर? बेशक योग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दे दी गयी हो एवं दुनिया के १७७ देश इसे अपना चुके हों, लेकिन भारत में ही इसको लेकर विरोध आदि के स्वर बेजा उठाये जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो व्यक्ति अनुशासित योग प्रक्रिया का जीवन में अनुकरण करता है, उसे सदैव स्वस्थ रहने का सुख प्राप्त होता है। वैश्विक स्वास्थ्य

एवं विदेश नीति के तहत प्रस्तावित किये गए इस एजेंडे में भी मूलतया यही बात कही गयी थी कि योग मानव जरुरत की तमाम उर्जाओं का श्रोत साधन है।

२१ जून को अन्तराष्ट्रीय योग दिवस मनाने सम्बन्धी इस घोषण में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये भी कहा गया कि योग को पूरी दुनिया में फैलाना एवं स्थापित करना जरुरी है। इस मामले में गौर करने वाली बात ये भी है कि इस दिवस को २१ जून को ही मनाने का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था। २१ जून को अन्तराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे वैज्ञानिकता ये है कि उत्तरी गोलार्ध में २१ जून सबसे बड़ा दिन होता है, लिहाजा यही दिन ज्यादा बेहतर हो सकता है। योग से जुड़े इस प्रस्ताव को पूरी दुनिया ने एकमत होकर स्वीकार किया। दरअसल कम संख्या में ही सही मगर भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमे मन में यह पूर्वाग्रह है कि हर परम्परागत संस्कार को वो रुढ़िवादी परम्परा मान बैठते हैं। ऐसी थोड़ी बहुत आलोचनाओं के बीच भारत ने एकबार विश्व को पारम्परिक स्वास्थ्य प्रणाली का पाठ पढ़ाया है और दुनिया ने इसे स्वीकार भी किया है।

योग के संदर्भ में अगर इसकी वैज्ञानिकता और भारतीय परम्पराओं में इसके वजूद की बात करें तो योग-प्रणाली का जिक्र विस्तार से तमाम वैदिक पुस्तकों में मिलता है। कई प्राचीन सभ्यताओं में योग क्रिया का प्रमाणित दर्शन प्राप्त होता है। प्राचीन भारत में योग तपस्वियों, योगियों एवं आम मनुष्यों के जीवन की दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। धीरे-धीरे बाहरी आक्रमणों एवं देश में अस्थिरिता की स्थिति ने इसके महत्व को कम कर दिया। लोग अंग्रेजी चिकत्सा पद्धति पर इतने निर्भर होते गए कि आरोग्य के स्थायी साधन के रूप में योग को शामिल करना ही भूल गये। योग हमे अस्वस्थ होने बचाता है जबकि दवाइयां हमे अस्वस्थ होने के बाद बचाती हैं। इस लिहाज से भी देखा जाय तो योग प्राथमिक जरूरत है। हालांकि वर्तमान में कुछ नाम जरुर प्रासंगिक हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थियों में भी योग को प्रचारित एवं प्रसारित करने की दिशा में काम किया है। ऐसे कुछ योग गुरुओं का जिक्र करें तो श्री तिरुमलाई कृष्णामचार्य, बीकेएस अयंगर, रामदेव कुछ ऐसे ही नाम है जिन्होंने योग को फिर से उच्चाईयों पर पहुँचाया है। आधुनिक दौर योग गुरु रामदेव ने योग शिक्षा को विश्व भर में फैलाने का एक बड़ा काम किया है। हालांकि समय-समय पर योग के महत्व को स्वीकार करने वाले युगपुरुष इस धरा पर जन्म लेते रहे हैं। मसलन, महात्मा गांधी खुद योग प्रणाली को स्वस्थ जीवन के लिए जरुरी मानते थे। चूंकि योग आपसे आर्थिक व्यय की मांग नहीं करता है बल्कि आपके जीवन का कुछ छण मात्र ही मांगता है। आज भले ही तमाम तरह के कृत्रिम व्यायाम के उपकरण आ गये हों लेकिन योग के में कृत्रिमता का जरा भी अस्तित्व नही था। योग पूर्णतया प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

आज जब एकबार फिर भारतीय वैदिक परम्परा का यह जीवन पद्धति विश्व पटल पर स्वीकार की जा रही है, तो इसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। विरोध को दरकिनार करते हुए सख्ती से यह सन्देश देने की जरुरत है कि हर बात में सेकुलरिज्म की खोखली सियासत नहीं चलेगी। ❍

दो साल का कामयाब सफर

हर्ष. वी पंत

नरेंद्र मोदी की सरकार २६ मई को केंद्र की सत्ता में दो साल पूरे कर लेगी। यह सरकार आम चुनावों में सिर्फ एक नेता नरेंद्र मोदी के दम पर मई २०१४ में भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में आई थी। इसके दो साल के कार्यकाल को देखें तो सरकार में सिर्फ मोदी ही नजर आते हैं। उनका विराट व्यक्तित्व अन्य नेताओं पर भारी दिखाई देता है। यहां तक कि विरोधियों में भी कोई दूसरा नेता उनकी लोकप्रियता के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। दरअसल २०१४ के आम चुनावों में कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल करने योग्य भी वह सीटें नहीं ला सकी। यह स्थिति मोदी के लिए मददगार साबित हुई है। जो कांग्रेस नेहरू-गांधी परिवार के नेतृत्व में देश के बड़े हिस्से पर छह दशकों तक शासन करती रही वह आज बदलते भारत में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। दरअसल परिवार के लोगों में वह धार नहीं बची है कि वे पार्टी को सशक्त नेतृत्व दे सकें।

दुनिया में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करने के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। जब अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कमोडिटी की गिरती कीमतों के कारण दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ने लगी हैं तब भारत की अर्थव्यवस्था फलफूल रही है। उम्मीद है कि २०१६ में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर ७.६ फीसद रहेगी। मोदी सरकार द्वारा देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के कारण भारत ने २०१५ में विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया।

वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के युवा उपाध्यक्ष और नेहरू-गांधी परिवार के उत्तराधिकारी राहुल गांधी आज उपाहास के पात्र बन गए हैं। वह अपने समर्थकों की तमाम कोशिशों के बाद भी न तो अपने नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन कर पा रहे हैं और न ही मोदी सरकार को प्रभावी रूप से चुनौती दे पा रहे हैं। वहीं दूसरे विपक्षी दलों का स्वरूप क्षेत्रीय है। उनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभाव नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी का प्रभाव पूरे देश में है। उन्होंने सोशल मीडिया का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके मौजूदा भारतीय राजनीति के महानायक के रूप में अपनी छवि बनाई है। यदि सफलता का पैमाना मुख्य विपक्षी पार्टी के सिकुड़ने को बनाया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार कांग्रेस के दशक भर के शासनकाल में हुए घोटालों को एक-एक कर सामने लाकर पार्टी को रक्षात्मक मुद्रा में लाने में सफल रही है। मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश के उन हिस्सों में भी अपना विस्तार कर रही है जहां दो साल पूर्व तक उसका अस्तित्व नहीं था। उदाहरण के रूप में देश के पूवरेत्तर राज्यों और दक्षिणी राज्य केरल में भाजपा का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। देखा जाए तो भाजपा सच्चे अर्थो में अखिल भारतीय पार्टी बन रही है। मोदी सरकार का भविष्य आर्थिक मोर्चे पर उसके

प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। हालांकि इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। विश्व की कई संस्थाओं ने ऐसा अनुमान व्यक्त किया है कि दुनिया में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करने के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। जब अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कमोडिटी की गिरती कीमतों के कारण दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ने लगी हैं तब भारत की अर्थव्यवस्था फलफूल रही है। उम्मीद है कि २०१६ में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर ७.६ फीसद रहेगी। मोदी सरकार द्वारा देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के कारण भारत ने २०१५ में विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। हालांकि देश में कुछ समय से निराशा का दौर रहा है, क्योंकि मोदी ने कोई बड़ा सुधारवादी कदम नहीं उठाया है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ऐसा ही एक प्रमुख सुधारवादी कार्यक्रम है, जो कि संसद में अटका पड़ा है। जीएसटी आने से उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे सभी अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो जाएंगे। अर्थात अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर पूरे देश में जीएसटी की एक दर लागू होगी। इसे एक अप्रैल, २०१६ से लागू किया जाना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से संसद के उच्च सदन में इसे पारित नहीं होने दिया। दरअसल जीएसटी कांग्रेस के दिमाग की उपज थी, लेकिन अब वह सोच रही है कि यदि वह इसकी राह में बाधक बनेगी तो मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल हो जाएगी। हालांकि राजग सरकार ने दूसरे कई अहम कदम उठाए हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल में फायदा पहुंचाएंगे। दीवालिया संबंधी कानून में संशोधन ऐसा ही एक कदम है। जाहिर है, यह कदम भारत में कारोबार करने को आसान बनाएगा। इसके साथ ही सरकार ने लाभार्थियों के खाते में सीधे नगद रूप में सब्सिडी की रकम भेजने और नकली लाभार्थियों को छांटने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना भी लागू की है। नौकरशाही की जवाबदेही सुनिश्चित कर सरकार ने गवर्नेंस पर खासा जोर दिया है। यह भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख है। एक अनुमान के अनुसार मोदी सरकार के आने के बाद भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म में तेज गिरावट दर्ज की गई है। विदेश नीति के मोर्चे पर केंद्र को सबसे ज्यादा सफलता मिली है। इसने दो साल के अल्प समय में अलग छाप छोड़ी है। मोदी भारत को अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थान दिलाना चाहते हैं। गुट निरपेक्षता की बात अब पीछे छूट गई है। दरअसल मोदी सरकार का मुख्य ध्यान समान विचारधारा वाले देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर है, ताकि भारत को आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर बढ़त दिलाई जा सके। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और दूसरे पड़ोसी देशों के बीच उपजे विवाद में भी भारत ने सशक्त भूमिका निभाई है। एक अलग पाकिस्तान नीति भी विकसित की गई है। इसके तहत नई दिल्ली इस्लामाबाद पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे पाकिस्तान के सहयोगियों का उपयोग कर रही है। सरकार के अभी दो साल ही हुए हैं। यह शासनकाल का शुरुआती दौर ही माना जाएगा। इसमें जनता की उम्मीदें कुलाचें मारती हैं। सरकार की नीतियों का प्रतिफल अगले तीन साल में परिलक्षित होगा। उसी के आधार पर उसके भविष्य की रूपरेखा बनेगी और २०१९ के चुनावों में उसकी दिशा तय होगी। ❍

(लेखक लंदन के किंग्स कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं, यह लेख दैनिक जागरण में प्रकाशित है)

मोदी सरकार का मूल्यांकन

डॉ. एके वर्मा

मोदी सरकार के दो वर्ष का मूल्यांकन करने के कई चश्मे हो सकते हैं। मोदी समर्थकों को सरकार का हर काम अच्छा और विरोधियों को नागवार और हास्यास्पद लगेगा, लेकिन निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए मोदी सरकार को उसके चुनावी वायदों के प्रति ईमानदारी, विभिन्न मंत्रलयों के कार्यो, पिछली सरकारों और प्रधानमंत्रियों से तुलना, देश-विदेश में छवि एवं राजनीतिक संस्कृति, कार्यशैली और प्रशासन में गुणात्मक परिवर्तनों के आधार पर जांचा-परखा जाना चाहिए। चूंकि मोदी सरकार अपने दो वर्ष की उपलब्धियां खुद ही गिना रही है इसलिए उनका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या उसका उद्देश्य लोकप्रियता हासिल करने का है या वास्तव में उसने देश के व्यापक हित में कुछ गंभीर नीतिगत पहल भी की है जिसके परिणाम चाहे देर से ही क्यों न आएं? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पांच-साल के एजेंडे को पूरा करने की कोई रणनीति बनाई थी? इस सवाल के जवाब में कहा जा सकता है कि संभवतः मोदी ने लोक-लुभावन निर्णयों से हटकर देश के दूरगामी हितों को साधने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने का मन बनाया था और अपने निर्णयों की स्वीकार्यता के लिए विभिन्न देशों, संघीय-इकाइयों और जनता से संवाद का रास्ता चुना। मोदी ने अब तक लगभग ४० देशों की यात्र की है और इन देशों के राष्ट्रपतियों-प्रधानमंत्रियों से मधुर संबंध बनाए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क में रह कर सीएम-पीएम टीम बनाने की कोशिश की और प्रगति कार्यक्रम द्वारा राज्यों के मुख्य-सचिवों से जन-समस्याओं और केंद्र-राज्य सरकारों के कार्यक्रमों की समीक्षा की। इसके अलावा वह हर महीने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम द्वारा जनता से रूबरू होते रहे। यह एक नई रणनीति है।

मोदी सरकार के मूल्यांकन का अर्थ है भारतीय लोक-प्रशासन का मूल्यांकन। अकादमिक दृष्टि से लोक-प्रशासन को दक्षता, प्रभावशीलता, मितव्ययिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के मानकों पर जांचा जा सकता है। क्या मोदी सरकार इन पर खरी उतरी है? सरकारी मशीनरी, उसकी कार्य-शैली और राजनीतिक-प्रशासनिक-संस्कृति में गुणात्मक परिवर्तन किए बिना इन्हें हासिल करना संभव नहीं। यूपीए-२ मंत्रिमंडल में ७१ मंत्रियों के मुकाबले मोदी मंत्रिमंडल में कम मंत्री हैं जिससे न केवल जनता के पैसे की बचत हो रही है वरन प्रति-मंत्री काम की मात्र में भी वृद्धि हुई है और वह भी बिना दक्षता एवं गुणवत्ता से समझौता किए। मोदी को राष्ट्रीय प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था और उसके तंत्र से भी वह बहुत वाकिफ नहीं थे, फिर भी वह कुछ हद तक पूरी मशीनरी को अपने ढंग से संचालित करने में सफल रहे हैं। केंद्र सरकार के दतरों की कार्यशैली में सुखद बदलाव आया है। विभिन्न मंत्रलयों में कार्यो को निपटाने की समय सीमा में कमी एवं कार्य उत्पादकता में बढ़ोतरी आदि ऐसे पहलू हैं जो जनता को दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन धीरे-धीरे जाने जाएंगे। सबसे प्रभावी परिवर्तन सरकारी मशीनरी में

भ्रष्टाचार से संबंधित है। केंद्रीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार काफी घटा है, लेकिन राज्यों के स्तर पर इतना भ्रष्टाचार है कि लगता नहीं कि निकट भविष्य में जनता को उससे कोई निजात मिलेगी। मोदी-सरकार ने संचार और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उपरोक्त सभी मानकों पर गंभीरता दिखाने की कोशिश की है। हालांकि राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण नीतिगत निर्णयों में वांछित गति नहीं मिली है।

मोदी सरकार के प्रतिरक्षा, वित्त, विदेश, ऊर्जा-कोयला, रेलवे, परमाणु-ऊर्जा एवं अंतरिक्ष आदि मंत्रालयों को तो प्रशंसा मिली ही है। इसके साथ ही सड़क और जहाजरानी, दूरसंचार एवं सूचना-प्रौद्योगिक, स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण, खनन एवं कृषि-मंत्रलय आदि भी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की नजर सभी मंत्रलयों पर रहती है। कुछ मंत्रियों और नौकरशाहों को इससे कष्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं इतनी मेहनत करते हैं कि किसी को शिकायत करने का अवसर नहीं मिलता। लोक-प्रशासन के विद्वान एफडब्ल्यू रिग्स ने विकासशील देशों की विकास अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए एक मॉडल बनाया था। उसमें इस बात का उल्लेख है कि विकसित समाजों में सरकार की संरचनाएं और उनके कार्य न केवल स्पष्ट और स्वायत्त होते हैं, वरन उनमें जबरदस्त तालमेल भी होता है। मोदी सरकार ने देश में व्यापार करने और नागरिकों को सरकार से संपर्क करने और काम करवाने में सुविधा दिलाने के क्षेत्र में जो पहल की है, वह एक तरह से रिग्स-मॉडल को भारत में लागू करने का प्रयास है। मोदी को ६८ वर्षो पुराना प्रशासनिक-ढांचा, प्रक्रियाएं और कार्य-संस्कृति विरासत में मिली जिससे रिग्स-मॉडल के आधार पर देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने में समय लगेगा, लेकिन अंतरिक्ष, प्रतिरक्षा, ऊर्जा आर्थिक-विकास और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो काम हुआ है उससे अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की साख एक विकसित देश के रूप में निखरी है।

मोदी ने चुनावों में समावेशी-राजनीति और समग्र-विकास का वायदा किया था जिसे उन्होंने सबका साथ-सबका विकास के नारे से व्यक्त किया था। जाहिर है कि अच्छे-दिन की कोई भी परिकल्पना इसी के तहत हो सकती है। कुछ दल और मोदी-विरोधी प्रायः अच्छे-दिन को लेकर मजाक करते हैं, लेकिन उन्हें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, क्या वे केवल अपने लिए ही अच्छे दिन चाहते हैं या उन तबकों के लिए भी जो गरीब और हाशिये पर हैं, जिनको एलपीजी गैस नहीं मिल रही थी, जिनके खेतों में पैदावार नहीं हो रही थी, जिन्हें काम नहीं मिल रहा था, किसी प्रकार की स्वास्थ्य-संबंधी सुरक्षा नहीं थी, बैंक के दर्शन दुर्लभ थे, कोई पहचान नहीं थी और जो आधारहीन थे? दूसरा, भारतीय जनता झूठे आरोप पसंद नहीं करती। उनका उल्टा ही असर होता है। इसका प्रमाण हम लोग लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं, जिसमें पिछले १२ वर्षो से मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगने के बावजूद जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दे दिया।

नेहरु, शास्त्री और इंदिरा-तीन प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो विभिन्न व्यक्तित्वों के प्रतिनिधि रहे। जवाहरलाल दार्शनिक और मिश्रित विचारधारा वाले, शास्त्री जी सरल, कुशल एवं कठोर प्रशासक और इंदिरा गांधी चाणक्यवादी व्यक्तित्व की धनी रहीं। मोदी में संभवतः इन तीनों का समावेश है, लेकिन वे तीनों प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों पर वैसा नियंत्रण नहीं रख पाए जैसा मोदी

ने रखा है। उन्होंने शुरू में ही भाई-भतीजावाद के संदर्भ में कठोर फैसले लेकर भ्रष्टाचार की आशंका को जड़ से खत्म कर स्पष्ट संदेश दे दिया। तब से आज तक किसी भी मंत्री या सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण सुनने में नहीं आया है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह निहायत अप्रत्याशित है और मोदी सरकार के दो वर्षो के कार्यकाल की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत में सरकार का इस तरह से पहली बार संचालन हो रहा है और इसे लोकतांत्रिक-शैली के कॉरपोरेटाईजेशन की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें पार्टी और सरकार के सामूहिक नेतृत्व का स्थान प्रधानमंत्री एक मुख्य-कार्यकारी के रूप में ले रहा है।

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

दैनिक जागरण में प्रकाशित लेख

जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निर्णय लेने की क्षमता सरकार की बड़ी उपलब्धि

भूपेन्द्र यादव

लोकसभा चुनाव में लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने के लिए भाजपा को वोट दिया। हमारी सरकार की दो साल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमने लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और पारदर्शी व्यवस्था कायम की है।

इससे लोकतंत्र में देश के लोगों का विश्वास पुनः जागृत हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमलोगों ने देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है, जो स्वयं निर्णय लेते हैं। इससे पहले जो सरकार थी, उसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था। भ्रष्टाचार मुक्त निर्णय का तो घोर अभाव था। मौजूदा सरकार इन तीनों चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है।

देश में लंबे समय से आर्थिक सशक्तीकरण का रास्ता बंद था। कांग्रेस ने १९७७ में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीबों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ना हमारी सरकार की उपलब्धि रही है। गरीबों को सशक्त करने की दिशा में सरकार चार बिंदु तय कर उस पर काम कर रही है।

पहला बिंदु, आर्थिक समावेशीकरण। समावेशीकरण का मतलब है कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उसका लाभ गरीबों तक पहुंचाएं। उन संस्थाओं से गरीबों को लाभ मिले। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, उसकी योजनाएं लोगों के पास पहुंचे। इसके लिए सबसे पहले जन-धन के अंतर्गत खाते खोले गये। दूसरी पहल हुई कि सरकारी धन में १४ हजार करोड़ रुपये की बचत कर उसका लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचाया गया। इसके लिए सरकार आधार कानून लेकर आयी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) को कानूनी रूप दिया गया। आर्थिक समावेशीकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम हुए।

दूसरा बिंदु, आर्थिक समावेशीकरण के साथ आर्थिक विकास भी होना चाहिए। आर्थिक विकास का सबसे बड़ा लाभ है रोजगार। आज ज्यादातर रोजगार मध्यम और असंगठित क्षेत्र में है। इसके लिए सरकार ने मुद्रा योजना शुरू की। साथ ही किसानों के लिए सरकार ने कृषि लोन को बढ़ा कर ९ लाख करोड़ कर दिया। उत्पादन से जुड़े २९ क्षेत्रों को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के लिए खोला गया। रक्षा क्षेत्र और रेलवे में एफडीआइ को मंजूरी दी गयी।

एक बात और ध्यान देने की है कि आर्थिक समावेशीकरण और आर्थिक विकास कभी अकेले नहीं हो सकते। उसके लिए आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आर्थिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन और बीमा योजनाएं शुरू की गयीं। किसानों के लिए कृषक सुरक्षा योजना शुरू हुई। ये योजनाएं पहले की सरकारों से अलग थीं। इन सब योजनाओं में कंटीन्यूटी यानी सततता है।

जब आप आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो इसमें सततता जरूरी है। विकास का लक्ष्य सततता से जुड़ा होना चाहिए। सततता के लिए आधाभूत ढांचे का विकास होना जरूरी है। इसीलिए मनरेगा को स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा गया, प्रधानमंत्री सड़क योजना पर ध्यान दिया गया। रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, ताकि सततता बनी रहे। इस सबका सबसे ज्यादा फायदा युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होगा। दुनिया में जब वैश्विक मंदी छायी हुई है, सरकार ने आर्थिक विकास के लिए घरेलू डिमांड को बढ़ाया। सरकार ने कुछ लक्ष्य तय किये, जैसे- सभी गांव में बिजली, सभी बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन, सभी गांव तक खाद्य सुरक्षा।

सरकार तय किये गये लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। विकास के इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए आयात-निर्यात में सुविधा के उपाय किये गये। पहले इसके लिए २३ तरह के फार्मेट होते थे, जिसे घटा कर तीन कर दिया। रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट दिया, जिससे एक ही रजिस्ट्रेशन से वह अपना काम कर सकें।

असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले लोगों के लिए यूनिक आइडेंडिटिफिकेशन नंबर दिया, जिससे उनके नौकरी बदलने के बाद भी उनकी राशि आसानी से ट्रांसफर हो सके। इस तरह मोदी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के साथ-साथ ट्रांसपेरेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम किया है।

दो साल की उपलब्धियों को आप देखेंगे, तो एक विकासोन्मुख सरकार और दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचनेवाली शासन व्यवस्था की स्थापना हमने की है। इसके साथ ही इकोनॉमिक इनक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक सेक्युरिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबलिटी की स्थापना हमारी सरकार ने की है। कृषि क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना आदि इस साल से लागू हुई है, जिसका लाभ अगले साल से किसानों को मिलना शुरू हो जायेगा।

बहुत सी योजनाएं दीर्घकालीन परिणाम और लक्ष्य को सामने रख कर बनायी गयी हैं। यह तय है कि हमारी सरकार ने जो काम किये हैं, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे।

○

(साभार : प्रभात खबर)

Corridors of Power: Two years of NDA... a lot better than UPA

Santosh Tiwari

Two years is a good enough time to judge the performance of a government, especially one that has come to power promising to completely change the way its predecessor worked.

In that sense, with the NDA government led by its star campaigner in the 2014 Lok Sabha polls, Prime Minister Narendra Modi, completing its two years in office on May 26, the UPA sympathisers have reason to ask 'what has changed from 2014', if more or less the same policies are being pursued.

But, on the ground, the reality is that the government functioning, especially in furthering social sector schemes and policy reforms, is a lot better than the UPA's last few years, even though in terms of investments and the economy picking up to usher in the so-called 'achhe din' promised by PM Modi, a lot of distance still needs to be covered.

This makes the setting perfect for a Congress-NDA battle on the achievements of PM Modi government as the ongoing Parliament session ends.

While the government machinery is all set to blow its trumpet of the successes through punch lines like 'Zara Muskara Do' as reported by The Indian Express, which will be the theme of a grand event to showcase NDA success stories, the opposition ranks will cry 'nothing has changed'.

That may be an unending debate, but net-net, the policy paralysis and despondency witnessed during the UPA regime due to the scams like 2G, coal and Commonwealth Games, among others, has taken a back-seat.

And though it is a fact that the NDA government has focused predominantly on fine-tuning and better implementation of the already existing policies and schemes under a repackaged brand to make them attractive and look new, the exercise has been fairly successful and has yielded good results.

Take the case of Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM). It is a refined and much better form of the UPA's Aadhaar-based direct benefit transfer (DBT) scheme that was launched in January 2013—the difference is, while the former failed, the latter is progressing well.

The core of the NDA's DBT model to disburse subsidies and all social sector

entitlements such as scholarships and pension, Jan-Dhan scheme, launched on August 28, 2014, boasts of 21.68 crore bank accounts now with R36,796 crore of deposits in them, along with 9.42 crore Suraksha Bima policies and 2.96 crore Jeevan Jyoti Bima policies.

Facing the threat of being left in the lurch as a scheme not to be touched because it was touted as a game-changer by the UPA regime, when it left office, Aadhaar has in fact been pursued by the NDA government with the zeal that is required for pushing such a scheme.

The number of Aadhaar enrolments surpassing the 100-crore mark last month, along with the enactment of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits, and Services) Act, 2016, has no doubt created one of the biggest reform platforms in the country.

Going by the success of the DBT in LPG, which helped the government save Rs 21,000 crore in the last two financial years, the implementation of Aadhaar-based DBT across all government social spending, including those on food and fertiliser, is expected to ensure substantial savings by curbing of the leakages that could be as high as 40-50% in some areas.

Another significant measure that will help farmers across the country far more than any of the vote-catching loan waivers is the liberal crop insurance schemes, as only 5% of them are covered by it because of higher premiums.

Under the new scheme announced by the government now, in which it will bear a major chunk of the premiums, farmers will have to pay a uniform premium of only 2% for all Kharif crops and 1.5% for all Rabi crops. For commercial and horticultural crops, the premium will be only 5%.

If the steps taken for improving the returns on the government's social sector spending are looking impressive, in case of dealing with some of the pending issues in areas like telecom also—such as the handling of spectrum shortage to improve telecom services and supporting Digital India and other government flagship schemes—there is a clear change visible in the approach.

Though the UPA government did the groundwork for releasing three carriers of 5MHz each in the 2100MHz band, it could not happen because the agreement with the defence ministry could not be worked out, that led to high bids in the 2015 auctions.

Not only the defence ministry has now been brought on board, making this spectrum available in the July auctions, the permission to allow spectrum trading and sharing has ensured the optimum use of the available spectrum

by telecom operators through tie-ups.

While these are bright spots and big hits, among others, including those in the power sector—such as promotion of LED bulbs and streamlining of coal block allocation and linkages—there are quite a few concern areas still left.

Despite PM Modi and finance minister Arun Jaitley hinting at the scrapping of the 2012 retrospective tax amendments a number of times, it is still in the statute and the two top cases, Vodafone and Cairn, no way near any resolution.

Unless these two cases are resolved, the ghost of retro tax will be around, even if the government doesn't take up any new cases.

Not being able to pass the Land Act changes to improve the land acquisition environment crippled by the 2013 Act and also the critical goods and services tax (GST) because of the lack of a majority in the Rajya Sabha is another big dampener for the reforms, and the NDA dispensation has failed to build enough

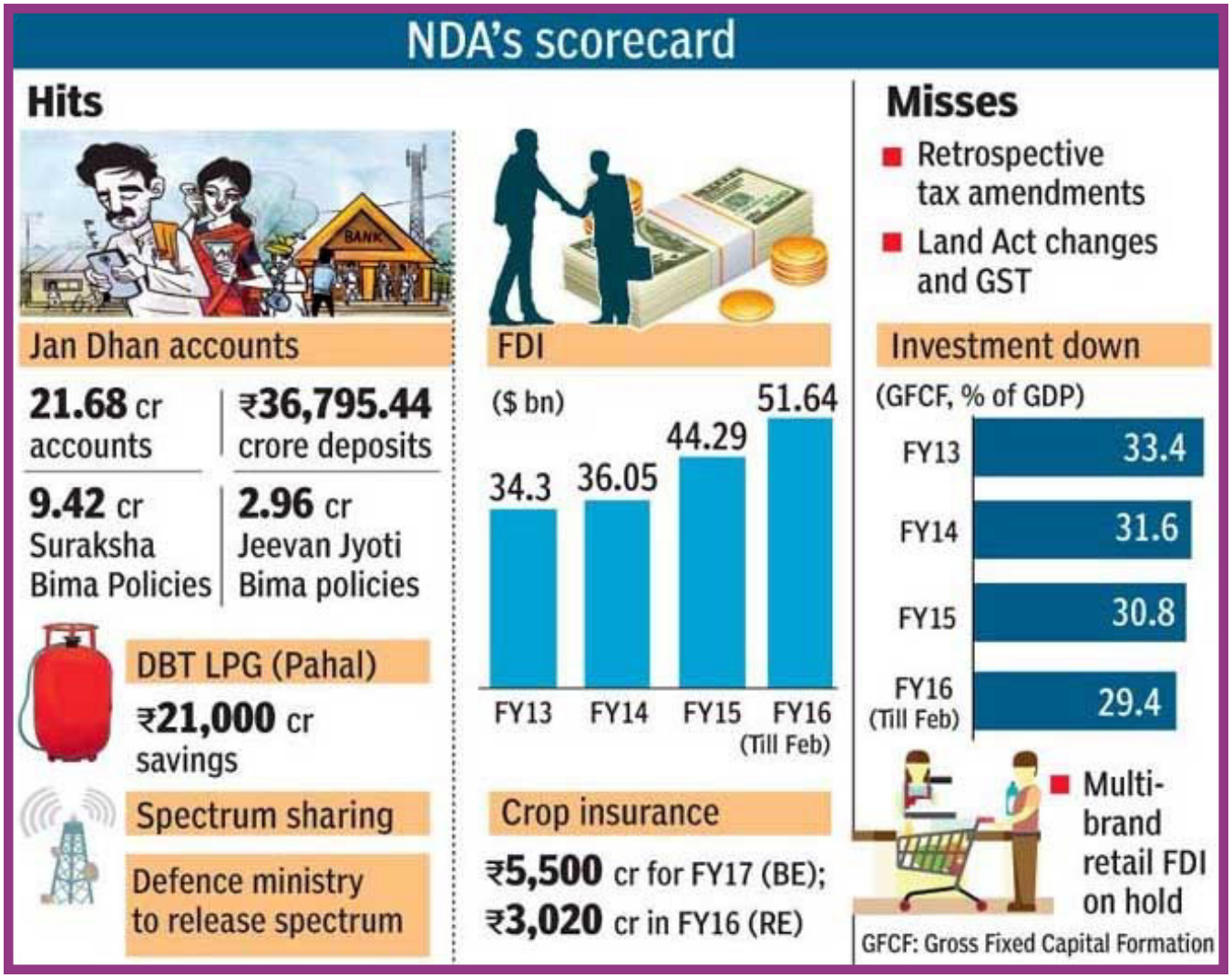

pressure on the Congress for co-opting the party to support these Bills.

If it succeeds in getting the Bankruptcy Bill passed in the Rajya Sabha this week, its scorecard on this will improve to a certain extent, as the Real Estate Bill has been already passed with the Congress support earlier in the session.

Indeed, the two years of the NDA government are more of a mixed bag in terms of results, but the overall atmosphere is far better than the UPA period—foreign direct investment in the country touching an all-time high of $51 billion in FY16 (till February) is an indication of that.

The biggest concern, however, of the investment not picking up still remains, and the situation is unlikely to improve at least in the next two years in any significant manner—private sector investment slowed down to 29.4% of GDP in FY16 from 38% in FY08, and capacity utilisation in factories is 71-74% for the past two years.

In the absence of any betterment of the global growth scenario in the near future, the government needs to target big reform measures like opening up multi-brand retail window for foreign investment and the passage of the GST and labour reform Bills in Parliament by finding ways to ensure Congress support to the reform legislations.

The road ahead in the next three years for the NDA government is going to be no less bumpy, even though with a GDP growth of around 7.5%, India is being considered a bright spot globally.

Courtesy: https://in.finance.yahoo.com/news/corridors-power-two-years-nda-004400474.html

Two years of transformation: On NDA's second anniversary, Ujjwala heralds smoke free acche din for India's poor

✍ **Amit Shah**

The Narendra Modi government will complete two years at the Centre this week, on May 26. Three key elements triggered NDA's spectacular 2014 election victory – taking development and prosperity to the lowest rung of society, eradication of corruption, and ensuring transparency and ease of doing business. While people may have varied opinions on the success of the Modi government on these three parameters, it is amply clear that we are moving decisively and strongly in these areas.

Gone are the days when the central government was besieged by allegations of rampant corruption in almost all spheres – from sale of spectrum to conducting Commonwealth Games and from purchase of helicopters to auction of coal mines. The last two years have seen a sea change as the NDA government has delivered spotless governance without even one serious allegation of corruption.

The Modi government's accountability towards the common man can be gauged from the fact that be it Indians trapped overseas, a helpless mother looking for a doctor for her ailing child in a train, or a housewife struggling to get a gas cylinder, help is just a tweet away, with no protocol or red tape intervening.

The government has also worked relentlessly to nurse the economy and ushered in a series of reforms to bring GDP growth back on track. Despite a slump in the global economy, those sustained efforts have reignited growth engines and India's GDP is likely to grow over 7.5% this financial year. The whole country has witnessed the opposition's continuous attempts to stonewall critical development oriented legislations like GST. Despite such roadblocks, the Modi government has not only strengthened the Indian economy but also re-established India's supremacy on the global scale.

Programmes like Jan Dhan Yojana, Mudra Yojana, Stand up India, Crop Insurance Scheme, Skill India and Make in India have benefited the common man. Gram Jyoti is rapidly laying infrastructure to electrify every single village in the country, while road construction – which had seen a significant

slowdown due to large scale corruption under UPA – is back on track with 18 km of national highways being built every day.

While the opposition alleges that our government has not been able to create new jobs, they conveniently forget that government jobs are not a panacea for unemployment. It is precisely because of this that Prime Minister Narendra Modi introduced schemes like Stand up India, Mudra Yojana, Make in India and Skill India. Thanks to these programmes, millions of skilled and semi-skilled workers and even those engaged in manual labour are getting employment opportunities. Under Stand up India, Dalits and tribals are getting a chance to turn entrepreneurs.

Before the NDA government came into power, the petroleum and natural gas ministry was largely associated with corporates and big ticket commercial interests. However, thanks to Modi's vision and petroleum minister Dharmendra Pradhan's tireless efforts, this key ministry has now become a public welfare ministry with programmes like PAHAL, "Give it Up" and Ujjwala Yojana.

A big chunk of the subsidy given by the Centre on cooking fuels always landed in the hands of middlemen. To curb this malpractice the petroleum ministry leveraged Jan Dhan Yojana to launch PAHAL, where subsidies were directly credited to bank accounts.

The scheme has been a roaring success as it put an end to rampant diversion of subsidised LPG for commercial use and embezzlement of funds meant for subsidy. As per latest figures, 15.02 crore LPG consumers have joined the scheme and subsidy of over Rs 32,307 crore has been directly credited to their bank accounts so far, saving the government the sizeable amount of Rs 14,672 crore in the last financial year.

With PAHAL meeting its aim, the PM announced "Give it Up" scheme and personally appealed to the well-heeled in society to voluntarily surrender their LPG subsidy. So far, over 1 crore LPG consumers have given up their LPG subsidy. Such has been the impact of the PM's appeal that not only the rich but even middle class families have enthusiastically participated in large numbers.

Both PAHAL and "Give it Up" have resulted in substantial savings, which are being utilised to provide cooking gas connections to the poor under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Under this scheme, the government is aiming to give free cooking gas cylinders to 5 crore families living below the poverty line by 2019.

According to the World Health Organization's 2012 report, 12 lakh Indians died due to smoke emanating from kitchens that use firewood or cow dung to cook food. Ujjwala will not only prove to be a blessing as far as the health of the poor is concerned but will also free women and children from the drudgery of collecting firewood from forests, making them safer.

Congress vice-president Rahul Gandhi had his photos taken at Kalawati's house, perhaps as part of his poverty tourism agenda. But Modi has seen poverty from close quarters and led a life where even basic resources were scarce. Schemes like Ujjwala will go a long way in wiping off tears of a poor woman triggered by everyday kitchen smoke, protect her from diseases and provide a smoke-free and clean environment to her children for their studies. These are real reforms. Perhaps, these are the signs of "acche din" under the Modi government.

Courtesy: http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/two-years-of-transformation-on-ndas-second-anniversary-ujjwala-heralds-smoke-free-acche-din-for-indias-poor/

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

https://web.facebook.com/spmrfoundation

https://twitter.com/spmrfoundation